दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

आज का विचार

जिनके स्वभाव में प्रेस बसा हो.. उनके दरवाजे पर खुशियां खुद ही चलकर आती हैं।

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ I बुधवार, 20 मई, 2026 वर्ष 24, अंक 120, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

मोदी सरकार युद्ध की आड़ में लोगों से विदेश एवं आर्थिक नीति की नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही: मान

देश में अघोषित लॉकडाउन लगाने के बजाय, प्रधानमंत्री को तेल, एलपीजी और सोने के भंडारों की वास्तविक स्थिति के बारे में लोगों को बताना चाहिए : मुख्यमंत्री

सिटी दर्पण संवाददाता

संगरूर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज खाड़ी युद्ध के हालात का फायदा उठाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र अपनी विदेशी और आर्थिक नीतियों की नाकामी को छुपाने के लिए इस युद्ध को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है और देश को जानबूझकर अघोषित लॉकडाउन की ओर धकेला जा रहा है। केंद्र द्वारा लोगों से बार-बार संयम बरतने की अपीलों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वैश्विक संकट से प्रभावित किसी भी अन्य देश ने अपने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल, गैस या सोना खरीदना बंद करने को नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को लोगों में दहशत और बेचैनी फैलाने के बजाय पूरे देश को भारत के भंडारों की वास्तविक स्थिति के बारे में बताना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीति के लिए उन पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिस नेतृत्व ने कभी भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा किया था, अब उसने देश को विश्व चेला बनाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का लाभ आम लोगों के बजाय उनके कारोबारी दोस्तों को ही हो रहा है। हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मोदी सरकार विदेश और आर्थिक नीति, दोनों पहलुओं पर पूरी तरह से नाकाम रही है, जिसके कारण देश में बेचैनी का माहौल है। केंद्र सरकार खाड़ी युद्ध से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता का आकलन करने में भी नाकाम रही है, जिससे देश में पूरी तरह से भगदड़ मच गई है।

मुख्यमंत्री ने ताना कसते हुए कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि युद्ध इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है और इसका प्रभाव केंद्र द्वारा जानबूझकर देश पर डाला जा रहा है, जबकि किसी अन्य पड़ोसी देश में स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व गुरु बनने का गर्व करने वाले प्रधानमंत्री ने अब देश को विश्व चेला बनाकर रख दिया है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार देश में लिए जाने वाले हर छोटे से छोटे फैसले के लिए अमेरिका में बैठे अपने दोस्तों से इजाजत लेती है। देश में अघोषित लॉकडाउन लगाने के बजाय, प्रधानमंत्री को

तेल, एलपीजी और सोने के भंडारों की वास्तविक स्थिति के बारे में लोगों को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश को इस तरह गैर-जिम्मेदाराना ढंग से नहीं चलाया जा सकता, जहाँ प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से समझदारी से खर्च करने की ताकीद की जाती है और वे खुद ऐशो-आराम में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री खुद विदेशी दौरों में व्यस्त हैं, लेकिन देशवासियों को विदेश यात्रा से परहेज करने की अपील करते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 14 सालों में किए गए इतने सारे विदेशी दौरों से हुई उपलब्धियों की जानकारी कभी भी मीडिया, देश या संसद के साथ साझा नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे लोगों को इन दौरों की उपलब्धियों के बारे में बताएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री अपने उद्योगपति मित्रों को इन विदेशी यात्राओं पर अपने साथ ले जाकर उन्हें निवेश के लिए सुविधा देते हैं। नतीजा यह है कि नरेंद्र मोदी के करीबी उद्योगपति दिनोंदिन अमीर हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देश गरीब होता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा, लोगों की समस्याओं का कोई अंत नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार लोग-विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। लोग भारी बोझ के नीचे दबे रहेंगे क्योंकि चुनाव मोड में व्यस्त होने के कारण केंद्र सरकार अभी-अभी कुंभकरणी नींद से जागी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर तीखी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एजेंसियां भाजपा के विंग के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार द्वारा इन एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने और उन्हें अपने निजी हितों के लिए भगवा पार्टी में शामिल करने के लिए किया जा रहा है। इन एजेंसियों के जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर, भाजपा देश में लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए बहुत नीचे गिर रही है।

हर जिले की जनपरिवाद और मासिक समीक्षा बैठकों में बड़ी शिकायतों की अनिवार्य समीक्षा की जाएं: सैनी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने म्हारी सड़क एप की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश

भूपेंद्र शर्मा

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाली जनपरिवाद बैठकों तथा उपायुक्तों द्वारा ली जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में म्हारी सड़क एप पर प्राप्त कम से कम एक बड़ी शिकायत की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाए। इसका उद्देश्य एप की उपयोगिता बढ़ाना तथा शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को सचिवालय में म्हारी सड़क एप से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एप का सेकेंड वर्जन दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। 11 मई को आयोजित एपीएक्स कमेटी की बैठक में सामने आए 17 प्रमुख बिंदुओं तथा उन पर उठाए गए कदमों की जानकारी हरसैक अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को दी गई।

बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा के विभिन्न विभागों की हुई मैपिंग के तहत अब तक कुल

1,43,065 सड़कों, जिनकी लंबाई लगभग 63,389 किलोमीटर है, की मैपिंग म्हारी सड़क एप पर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने सड़कों की जियो-टैगिंग का कार्य तेजी और सटीकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों के अनुसार एप के माध्यम से अब तक 31,939 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री को एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर एप डाउनलोड की स्थिति की भी जानकारी दी गई। बैठक में पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, हरसैक सहित विभिन्न विभागों के लगभग 25 अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से एप पर प्राप्त शिकायतों और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि म्हारी सड़क एप के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। विशेष रूप से एग्रीगेटर कंपनियों जैसे ओला और उबर से जुड़े टैक्सी चालकों को भी ऐप के लाभ बताए जाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के आरटीओ कार्यालयों में टैक्सी पासिंग के लिए आने वाले चालकों के मोबाइल में भी यह एप डाउनलोड करवाया जाए, ताकि वे प्रदेश की सड़कों की स्थिति से संबंधित जानकारी सीधे सरकार और विभागों तक पहुंचा सकें।

एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने म्हारी सड़क एप और मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजी गई सड़क संबंधी शिकायतों पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि डीएलपी (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) के तहत कोई ठेकेदार सड़क की मरम्मत नहीं करता है, तो उसकी बैंक गारंटी जब्त की जाए। यदि किसी फर्म पर तीन बार ऐसी कार्रवाई होती है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। बैठक में भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और पानीपत जिलों की कुछ ऐसी शिकायतों का भी उल्लेख किया गया, जिन्हें संबंधित विभागों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर बार-बार दूसरे विभागों को ट्रांसफर किया गया। लंबित पड़ी इन शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री ने एक दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

शॉर्ट-टाइम टेंडर और बॉर्डर क्षेत्रों पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि म्हारी सड़क एप पर आने वाली शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में टेंडर प्रक्रिया में अक्सर अधिक समय लग जाता है, इसलिए अब शॉर्ट-टाइम टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके तहत बिड सबमिशन के 10 दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को जल्द बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अंतरराज्यीय बॉर्डर क्षेत्रों की सड़कों की विशेष देखभाल, मरम्मत और निर्माण कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी

मुख्यमंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलों और दीवारों पर पेंटिंग एवं सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए जाएं, ताकि सड़क अवसंरचना अधिक आकर्षक दिखाई दे। साथ ही संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्रों की सड़कों का नियमित निरीक्षण करें और समय पर रखरखाव सुनिश्चित करें।

योगी के विजन ने यूपी को बनाया एक्सप्रेसवे स्टेट, विकास की नई इबारत लिख रहा प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 1900 किलोमीटर से अधिक हुआ एक्सप्रेसवे नेटवर्क, मिल रही सहूलियत

एजेंसी (हि.स.)

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। कभी पिछड़ेपन और विकास की धीमी रफ्तार के लिए पहचाने जाने वाला यूपी आज एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में नई पहचान बना चुका है। गत 09 वर्षों में यूपी में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क 1900 किलोमीटर से अधिक हो गया है। यह आर्थिक बदलाव की नई कहानी को दर्शा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और निमार्णाधीन गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। गाजीपुर से दिल्ली तक का सफर अब लगभग 10 घंटे में सिमट गया है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे ने यात्रा समय को लगभग आधा कर दिया है। योगी सरकार ने खुद को केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक विकास का मजबूत मॉडल तैयार किया है। सरकार सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और स्पीड के ट्रिपल-एस मॉडल के तहत एक्सप्रेसवे के किनारे विभिन्न औद्योगिक पार्क और क्लस्टर विकसित कर रही है, जो आने वाले समय में प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखेंगे, जिससे लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रीढ़ बन चुका है। झांसी और चित्रकूट जैसे क्षेत्रों में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना से रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

गांव से शहर तक पहुंचा विकास का लाभ

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जा रही है कि एक्सप्रेसवे का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। संपर्क मार्गों और ग्रामीण सड़कों के जरिए छोटे कस्बों और गांवों को भी इससे जोड़ा गया है। किसान अब अपने कृषि और दुग्ध उत्पाद कम समय में शहरों तक पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद करीब 36 लाख करोड़ रुपये हो गया है। लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के संभावित निवेश प्रस्ताव यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं।

नक्सल मुक्त बस्तर को विकास और समृद्धि का मॉडल बनाएंगे : अमित शाह

एजेंसी (हि.स.)

जगदलपुर

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और अगले पांच वर्षों में बस्तर को नक्सल मुक्त कर विकास, समृद्धि और संतृप्ति के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब बस्तर में विश्वास और भविष्य के प्रति आशा का वातावरण दिखाई दे रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि बस्तर के विकास की कार्ययोजना में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

सरकार केवल सड़क, भवन और अन्य आधारभूत संरचना विकसित करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार सृजन, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आदिवासी समुदाय की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि अब सेवा डेरों के माध्यम से ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बैंकिंग, डिजिटल सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सुविधाओं की पहुंच बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि बस्तर देश के अन्य हिस्सों की तुलना में विकास की दौड़ में 30-40 वर्ष पीछे रह गया है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार यहां आधारभूत संरचना, सिंचाई परियोजनाएं, रेलवे कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है।

उन्होंने बस्तरवासियों और विशेष रूप से आदिवासी समाज से अपील करते हुए कहा कि जो लोग दशकों तक बंदूक के साए में बस्तर को रोककर रखना चाहते थे, उनके बहकावे में न आएं।

दिल्ली बनेगा विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था का उदाहरण: गडकरी

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को डीएनडी-फरीदाबाद- सोहना नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली को यातायात दबाव और जाम की समस्या से मुक्त करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी। इसके तहत नए नियंत्रित राजमार्गों, रिंग रोडों, सुरंगों के माध्यम से दिल्ली को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा,

माल परिवहन व्यवस्था अधिक सक्षम बनेगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी तथा पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी भी उपस्थित रहे।

गडकरी ने कहा कि नए नियंत्रित राजमार्गों, रिंग रोडों, सुरंगों और ऊपरी गलियारों के माध्यम से दिल्ली को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। विकास परियोजनाओं की लागत बढ़ने के बावजूद कार्यों की गति कम नहीं हुई है और इनसे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये की सड़क मूलभूत ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अब तक लगभग 87 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1050 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा 13 हजार करोड़ की लागत से 225 किलोमीटर लंबे मार्गों पर निर्माण कार्य जारी है। वहीं, 34,500 करोड़ रुपये की आगामी परियोजनाओं पर भी काम प्रस्तावित है। साथ ही 25 से 30 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में यातायात दबाव कम करना, भीड़ और प्रदूषण घटाना, ईंधन की बचत करना, माल परिवहन लागत कम करना और तेज स्थानीय यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

कुछ विश्वविद्यालय केवल संस्थान होते हैं और कुछ विश्वविद्यालय सभ्यता के प्रतीक होते हैं, नालंदा इसी दूसरी श्रेणी में आता है: डॉ. पी.के. मिश्रा

एजेंसी

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने आज बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने 14 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 221 स्नातकों को उपाधि प्राप्त करने पर बधाई दी और उनकी शैक्षणिक उपलब्धि को कड़ी मेहनत और लगन से हासिल किया गया मील का पत्थर बताया। डॉ. मिश्रा ने प्राचीन नालंदा महाविहार को इतिहास के सबसे महान शिक्षण केंद्रों में से एक बताते हुए कहा, कुछ विश्वविद्यालय केवल संस्थान होते हैं और कुछ ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो सभ्यता के प्रतीक होते हैं। नालंदा इसी दूसरी श्रेणी में है।

डॉ. मिश्रा ने इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व का उल्लेख करते हुए नालंदा के इस मूल दर्शन पर बल दिया कि ज्ञान हमेशा संवाद के साथ जुड़ा होना चाहिए, यह विभिन्न विषयों से जुड़ा होना चाहिए और मानवता के व्यापक कल्याण की दिशा में निर्देशित होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के नए हरित 'नेट जीरो' कैंपस की सराहना की जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इस संदर्भ में उन्होंने बोधगया को भी याद किया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। डॉ. मिश्रा ने कहा, वास्तव में पूरे एशिया महाद्वीप को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत लाभ हुआ है। मुझे विश्वास है कि इस महान विश्वविद्यालय से ज्ञान का प्रसार दूर-दूर तक महाद्वीपों में होगा।

डॉ. मिश्रा ने वर्तमान युग के व्यापक संदर्भ पर बात करते हुए 21वीं सदी के उस विरोधाभास की ओर संकेत किया जिसमें मानव के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व तकनीकी क्षमताएं मौजूद हैं। हालांकि, इस दौर में जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक संघर्ष और समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण से जुड़ी गहरी अनिश्चितताएं भी हैं। डॉ. मिश्रा ने इस बात पर बल दिया कि, मानवता के सामने मुख्य प्रश्न केवल यह नहीं है कि क्या हम और अधिक जानकारी या तकनीक का सृजन कर सकते हैं बल्कि यह है कि क्या ज्ञान प्रज्ञा, नैतिकता, करुणा और मानवीय उत्तरदायित्व से जुड़ा रहेगा।

डॉ. मिश्रा ने नालंदा की मूलभूत बौद्धिक परंपराओं पर विचार करते हुए उसके अंतर्अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख किया। उन्होंने वाद अर्थात गहन संवाद और अन्वेषण को विकसित करने के महत्व पर बल दिया। इसे उन्होंने आधुनिक बौद्धिक निष्क्रियता से दूर होने का प्रभावी समाधान बताया। उन्होंने सतर्क करते हुए कहा कि यद्यपि तकनीक हमें किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल प्रदान कर सकती है परन्तु, वह नैतिक तर्कशक्ति और उत्तरदायित्व के आचरण का स्थान नहीं ले सकती, न ही वह मानवीय अर्थ, पीड़ा, गरिमा या आकांक्षाओं को पूरी तरह से समझ सकती है। डॉ. मिश्रा ने दृढ़तापूर्वक कहा, सभ्यताओं का पतन तब नहीं होता जब वे जानकारी खो देती हैं बल्कि तब होता है जब वे चिंतन और स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने की क्षमता खो देती हैं।

- **पीएम के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने बिहार के राजगीर में नालंदा विवि के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया**
- **पूरे एशिया महाद्वीप को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत लाभ हुआ है, मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से ज्ञान का प्रसार काफी दूर-दूर तक महाद्वीपों में होगा: डॉ. मिश्रा**
- **सभ्यताओं का पतन तब नहीं होता जब वे जानकारी खो देती हैं बल्कि तब होता है जब वे चिंतन और स्वतंत्र सोच की क्षमता खो देती हैं: डॉ. पी.के. मिश्रा**

डॉ. मिश्रा ने औपनिवेशिक शासन के ऐतिहासिक प्रभाव पर चर्चा करते हुए बताया कि इसने किस प्रकार बौद्धिक ढांचों में परिवर्तन किया तथा आयुर्वेद, बौद्ध ज्ञानमीमांसा और अर्थशास्त्र जैसी समग्र स्वदेशी परंपराओं को हाशिए पर डाल दिया। उन्होंने 21वीं सदी को बौद्धिक रूप से उपनिवेशवाद के प्रभाव से मुक्त काल बनाने का आान किया और सभ्यतागत आत्म-विश्वास को पुनः प्राप्त करने पर बल दिया ताकि स्वदेशी विचारों और ज्ञान प्रणालियों का वैश्विक विमर्श में योगदान हो सके। उन्होंने कहा, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भारत के इस विश्वास को दर्शाता है कि खुलापन, विविधता, संवाद और अन्वेषण मानवता के भविष्य के लिए अनिवार्य हैं। डॉ. मिश्रा ने सीखने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का विस्तार से वर्णन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहु-विषयक शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के औपचारिक एकीकरण पर दिए गए बल का उल्लेख किया। उन्होंने देश की विशाल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से जुड़ी पहलों के बारे में भी बताया, जैसे 'राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन' और 'पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय' जिसमें लाखों प्राचीन ग्रंथों का सक्रिय रूप से प्रलेखन किया गया है और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुरुपयोग से बचाया गया है। डॉ. मिश्रा ने ज्ञान प्राप्ति तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को कम करने के प्रयासों पर विस्तार से बताते हुए स्वदेशी भाषाओं के अनुवाद के लिए 'भाषिणी' जैसी एआई-संचालित पहलों और वैश्विक शोध पत्रिकाओं तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिजाइन किए गए 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' कार्यक्रम का उल्लेख किया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी, विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) श्री रुद्रेंद्र टंडन, विश्वविद्यालय के शासी निकाय के सदस्य, अकादमिक परिषद के सदस्य, संकाय सदस्य तथा हमारे साझेदार देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के विशिष्ट प्रतिनिधि उपस्थित थे।

महंगाई और ईंधन संकट पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला

'केंद्र की ढुलमुल विदेश नीति और गिरता रुपया देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा'

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने देश में लगातार बढ़ती महंगाई, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और पेट्रोलियम पदार्थों के आसमान छूते दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

शिमला में जारी एक तीखे बयान में उन्होंने केंद्र सरकार पर चौतरफा निशाना साधते हुए कहा कि आज देश की आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है, जबकि केंद्र सरकार केवल ज्ञान बांटने और अपनी नाकामियों को छुपाने में व्यस्त है। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए इसे राज्य सरकार की नीतियों पर जनता की पक्की मुहर बताया है। आसमान छूती महंगाई से आम जनता बेहाल, ईंधन संकट ने बढ़ाई रसोई की चिंता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण आज आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुएं उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं।

❍ कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने नगर निकाय चुनावों में बंपर जीत का दावा किया

खाद्यान्न, दूध, ब्रेड और हरी सब्जियों जैसी आवश्यक चीजों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे मध्यम और गरीब वर्ग का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आज प्रदेश और देश के कोने-कोने में लोगों को खाना बनाने के लिए ईंधन की चिंता सताने लगी है। सिलेंडर के लिए लंबी कतारें और बढ़ती कीमतें इस बात का प्रमाण हैं कि केंद्र सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह आंखें मूंदे बैठी है। विनय कुमार ने युवाओं के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि देश में बेरोजगारी का ग्राफ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। रोजगार के अवसर पैदा करने के बजाय सरकार इस गंभीर विषय से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जिससे युवा वर्ग में गहरा असंतोष और निराशा है। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने विदेश नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की ढुलमुल और कमजोर विदेश नीति के कारण ही आज देश के सामने गंभीर ईंधन संकट खड़ा हुआ है।

उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री देश की जनता को तेल और एलपीजी की खपत कम करने (बचत करने) की नसीहत देते हैं, वे खुद लगातार विदेश दौरों पर व्यस्त हैं और देश की आंतरिक समस्याओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। विनय कुमार ने आर्थिक मोर्चे पर विफलताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की लगातार गिरती कीमत और देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था बेहद चिंता का विषय बन चुकी है। कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार को तुरंत अमेरिकी दबाव से मुक्त होकर दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों से स्वतंत्र रूप से बातचीत करनी चाहिए। सरकार को देश में कच्चे तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि ईंधन के दाम कम हों और सीधे तौर पर महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने अंत में कहा कि यह चुनाव परिणाम इस बात का सीधा प्रमाण है कि हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति को राज्य में कोई जगह नहीं मिलने वाली है।

सीएम सलाहकार वानी ने विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की

जम्मू। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत चल रहे प्रमुख अवसंरचना एवं विकास कार्यों की व्यापक समीक्षा की और आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले सभी प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरे के दौरान सलाहकार के साथ परियोजना निदेशक डॉ. देवांश यादव, सुनील थुस्सू और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सलाहकार ने सबसे पहले फेम-कफपहल के अंतर्गत विकसित किए जा रहे टाटा ई-बस डिपो का दौरा किया और पीएम ई-बस सेवा परियोजना से संबंधित चल रहे कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जम्मू शहर में पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिक बस अवसंरचना विकसित की जा रही है। शहरी परिवहन अवसंरचना के आधुनिकीकरण में जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रयासों की सराहना करते हुए नासिर असलम ने अब तक की प्रगति की प्रशंसा की और अधिकारियों को पीएम ई-बस सेवा परियोजना के शीघ्र पूरा होने और उद्घाटन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी पहल जम्मू को एक स्वच्छ, हरित और अधिक व्यवस्थित शहरी केंद्र में बदल रही है और सभी विकास परियोजनाओं को मिशन मोड में तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। बाद में सलाहकार ने आगामी 'वेस्ट टू वंडर पार्क' परियोजना का दौरा किया और पुनर्चक्रित अपशिष्ट सामग्री से निर्मित कलात्मक स्मारकों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की।

पंजाब और डार्क वेब से हिमाचल पहुंच रहा नशा : ओपी शर्मा

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

नशा निवारण बोर्ड के पूर्व संयोजक कम एडवाइजर ओम प्रकाश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नशे को रोकने के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही और प्रदेश में पंजाब तथा पाकिस्तान से बड़े स्तर पर नशा पहुंच रहा है। साथ ही डार्क वेब के जरिए भी नशे की सप्लाई होने का दावा किया। शिमला में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में ओपी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद करीब दो साल तक नशा निवारण बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 में नियमों को नजरअंदाज कर एक राजनीतिक व्यक्ति को बोर्ड का संयोजक कम एडवाइजर बना दिया गया, जबकि इस पद पर अनुभवी लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि केवल पुलिस के भरोसे नशे की समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की भागीदारी और जागरूकता अभियान जरूरी हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को नशे से बचाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम नहीं चला रही है।

ओपी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में नशे के कारण बड़ी संख्या में युवाओं की मौत हो रही है, लेकिन सरकार इसे रोकने में प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि केवल बड़ी रैलियां आयोजित करने से नशा खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके लिए जमीनी स्तर पर लगातार काम करने की जरूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि नशा तस्करी की ह्वाईकवर्ड लिंकेजह यानी सप्लाई नेटवर्क तक पहुंचने पर पर्याप्त काम नहीं हो रहा। शर्मा के मुताबिक पुलिस विभाग में मैनपावर की भी भारी कमी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1200 कमांडो भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक वह योजना जमीन पर नजर नहीं आई।

कठुआ पुलिस ने मात्र 4 दिनों में सुलझाई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी, आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

रूप सिंह हत्या मामले में कठुआ पुलिस ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए ब्लाइंड मर्डर केस को मात्र 4 दिनों में सुलझाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस ऑपरेशन की निगरानी एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के नेतृत्व में की गई।

एसएसपी कठुआ ने बताया कि 15/16 मई 2026 की दरम्यानी रात को थाना लखनपुर को गांव धन्ना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की सूचना मिली। मृतक की पहचान रूप सिंह के रूप में हुई जो पेशे से ठेकेदार था। सूचना मिलते ही थाना लखनपुर में एफआईआर नंबर 51/2026 धारा 103 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक पूछताछ की। वहीं जांच के दौरान सरदार सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी त्रिडवां तहसील व जिला कठुआ घटना के बाद से लापता पाया गया जिससे उस पर शक गहरा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मृतक के पास मजदूरी करता था और उसके 6000 बकाया थे। इसी रकम को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गुस्से और रंजिश में आकर 15/16 मई की रात अपने पिता की 12 बोर बंदूक लेकर रूप सिंह के घर पहुंचकर खिड़की के पास सो रहे रूप सिंह पर गोली चला दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन कर जम्मू-कश्मीर समेत पड़ोसी राज्यों में लगातार छापेमारी की।

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल रही केंद्र सरकार : जगत सिंह नेगी

शिमला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पेट्रोल और डीजल के दामों में पांच दिनों के भीतर दूसरी बार हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रही है, लेकिन इसका फायदा देश की आम जनता को नहीं मिल रहा। इसके उलट लगातार टैक्स और सेस बढ़ाकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय हालात और युद्ध का हवाला देकर ईंधन के दाम बढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ऐसे हालात लंबे समय से बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत रूस सहित कई देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है और सरकार को कम कीमत पर तेल मिल रहा है। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सस्ते दामों पर खरीदे गए कच्चे तेल को रिफाइन कर दूसरे देशों को निर्यात कर रही है, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी जा रही। नेगी ने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को अपेक्षाकृत कम कीमतों पर तेल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि भारत में आम लोगों को महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते टैक्स और सेस के कारण लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

जीत के झूठे आंकड़े पेश कर पंचायत चुनावों को प्रभावित करना चाहते मुख्यमंत्री सुक्खू: जयराम

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के झूठे आंकड़ों से जनता को गुमराह कर रहे हैं। ताकि पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि गारंटियों, योजनाओं को लेकर झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री अब चुनाव रिजल्ट पर भी झूठ बोल रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ विदाई की शहनाई बज चुकी है, जिसका शोर सुनने का साहस मुख्यमंत्री में नहीं है।

जयराम ठाकुर ने मंगलवार को अपने सराज प्रवास के दौरान शंकरदेहरा में जिला परिषद ब्रयोगी वार्ड एवं जरोल में जिला परिषद रोड़ वार्ड में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में उन्होंने संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत व गंभीर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी 4 वार्डों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की शानदार और ऐतिहासिक विजय पूरी तरह से निश्चित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत के आंकड़ों को सोशल मीडिया और मीडिया के सामने अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। जिससे आगामी पंचायतीराज चुनावों में जनता द्वारा उनका सूपड़ा साफ होने से पार्टी को बचा सकें। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अधिकृत लिस्ट जारी करके बिना सिंबल के अपने मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे।

जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

संक्षिप्त-समाचार

बारामूला में बी.के. ट्रेडर्स गोदाम में लगी भीषण आग हार्डवेयर और सैनिटरी सामान पूरी तरह जलकर राख

बारामूला। बारामूला के कनली बाग इलाके में स्थित बी.के. ट्रेडर्स ग्रुप के गोदाम मे देर रात भीषण आग लग गई। इस दौरान हार्डवेयर और सैनिटरी सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग लगने से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। गोदाम मालिक के अनुसार इस हादसे में लगभग 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और गोदाम में रखा 100 प्रतिशत सामान तबाह हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार जैसी ही आग लगने की सूचना मिली तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों, जम्मू-कश्मीर पुलिस तथा भारतीय सेना ने मिलकर राहत और बचाव कार्य चलाया जिसकी बदौलत आसपास की रिहायशी बस्ती को बचा लिया गया। हालांकि गोदाम पूरी तरह जल गया लेकिन समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि बी.के. ट्रेडर्स ग्रुप में करीब 30 से 40 लोग काम करते थे जिनका रोजगार इसी फर्म से चलता था। घटना के बाद कई मजदूर भावुक नजर आए। कुछ कर्मचारियों ने कहा कि उनका रोजगार इसी गोदाम से चलता था। यह सिर्फ बी.के. ट्रेडर्स का गोदाम नहीं जला बल्कि उनके घर जल गए हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने 93 लाख रुपये की भूमि धोखाधड़ी मामले में तलाशी ली

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने प्रवासी भूमि और खड़े पेड़ों से संबंधित फर्जी समझौतों से जुड़े 93 लाख रुपये के भूमि धोखाधड़ी मामले में बडगाम जिले में घर की तलाशी ली। अधिकारियों के अनुसार पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू कश्मीर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 340 और 61(2) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 17/2026 के संबंध में बडगाम के सेमसान इलाके में तलाशी ली गई। यह मामला धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें जावलपोरा, बडगाम के आरोपी गुलाम मोहि-उद-दीन डार और बेंगलुरु उत्तर, कर्नाटक के सूम नाथ कौल जो वर्तमान में जानीपुर जम्मू में रहते हैं शामिल हैं। जांच से पता चला कि शिकायतकर्ता को कथित तौर पर फर्जी समझौतों के माध्यम से पुलवामा जिले के द्रुसु में पांच कनाल प्रवासी भूमि और बिजबेहरा में 300 खड़े पेड़ खरीदने के लिए प्रेरित किया गया था।

टौंस नदी में समाई सिरमौर की बोलेरो, चालक समेत अन्य की तलाश जारी

नाहन। जनपद देहरादून के थाना त्यूणी क्षेत्र के अंतर्गत तहसील चकराता के सैंज-पाटन के बीच मंगलवार सुबह एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हिमाचल नंबर की एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 150 से 200 फीट गहरी खाई में गिरते हुए उफनती टौंस नदी में समा गई। हादसे के बाद से वाहन चालक सहित उसमें सवार संभावित अन्य लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीण संयुक्त रूप से नदी के तेज बहाव के बीच बड़े पैमाने पर राहत एवं खोज अभियान चला रहे हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह लगभग 9:30 बजे मिनस बैरियर पर तैनात कर्मचारी आकाश ने त्यूणी थाना पुलिस को सूचना दी कि सैंज-पाटन के बीच एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सीधे नदी में जा गिरा है। सूचना मिलते ही थाना त्यूणी प्रभारी निरीक्षक अश्वनी बलूनी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम को भी तत्काल घटनास्थल पर भेजा गया। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन की पहचान बोलेरो संख्या HP85अअ-0548 के रूप में हुई है। इस बदनसीब वाहन को खुशीराम (उम्र लगभग 45 वर्ष) पुत्र लायक राम, निवासी ग्राम चियोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) चला रहे थे। खुशीराम पेशे से ठेकेदार थे और मंगलवार सुबह ही अपने घर से चौपाल-मड़ोग (हिमाचल प्रदेश) की ओर काम के सिलसिले में जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सैंज-पाटन के पास तीखे मोड़ पर वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और पलक झपकते ही गहरी खाई को चीरते हुए टौंस नदी में जा गिरा। पुलिस को अंदेशा है कि ठेकेदार खुशीराम के अलावा गाड़ी में कुछ मजदूर भी सवार हो सकते थे, हालांकि देर शाम तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी।

नाहन में बीच सड़क पर खूनी झड़प, महिला और बुजुर्ग ने एक-दूसरे पर दर्ज कराया क्रॉस केस

नाहन। जिला मुख्यालय नाहन के पुलिस थाना में दो पक्षों की शिकायतों के आधार पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का एक सनसनीखेज क्रॉस केस दर्ज हुआ है। इस मामले में एक तरफ से एक महिला ने और दूसरी तरफ से बिजली विभाग के एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग कर्मचारी ने एक-दूसरे पर सरेआम रास्ता रोककर गाली-गलौज, बेइज्जती करने और ईंट उठाकर जानलेवा हमला करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की क्रॉस एफआईआर दर्ज कर मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना नाहन में दर्ज पहली शिकायत में अमरपुर मोहल्ला की निवासी संगीता पत्नी रोहित ने आरोप लगाया है कि बीते रविवार (17 मई) की शाम वह अपने पति के साथ मंदिर जा रही थीं। रास्ते में मदन मोहन और उनके बेटे ने उन्हें अचानक रोक लिया और सरेआम लोगों के सामने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए घोर बेइज्जती की। संगीता का आरोप है कि बहसबाजी के दौरान मदन मोहन ने पीछे से उनके पति को दबोच लिया, जबकि मदन मोहन के बेटे ने पास ही पड़ी एक ईंट उठा ली। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब वह बीच-बचाव कर झगड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रही थीं, तो उसी दौरान मदन मोहन का पैर फिसल गया और वह मुंह के बल सड़क पर गिर गए। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी अक्सर उनके घर पर आकर भी गाली-गलौज करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं।

हिमाचल में मैदानों से पहाड़ों तक बढ़ी तपिश 21-22 मई को आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मई महीने की गर्मी अब पहाड़ों तक महसूस होने लगी है। राज्य के मैदानी और निचले इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं शिमला, मनाली और कल्पा जैसे ठंडे शहरों में भी रातें सामान्य से ज्यादा गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को प्रदेश में मौसम साफ बना है और निचले इलाकों में सुबह से ही तेज धूप निकली। हालात ऐसे रहे कि कई जगहों पर सुबह 10 बजे तक लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है।

बीते 24 घंटों में सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी औसतन 2.2 डिग्री अधिक दर्ज हुआ है, जिससे रातों की गर्मी भी बढ़ गई है। राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा है। कल्पा में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मनाली में रात का तापमान 13.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक है। इन आंकड़ों से साफ है कि पहाड़ों के ठंडे इलाकों में भी इस बार असामान्य गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने 25 मई तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 19 और 20 मई को राज्य में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और केवल कुछ स्थानों पर हल्की गतिविधियां हो सकती हैं। 21 और 22 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 से 25 मई तक भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी।

रेणुका जी में रास्ता मांगना पड़ा भारी, ददाहू के युवक पर डंडों से हमला, हाथ में फ्रैक्चर

नाहन। जिला सिरमौर के पुलिस थाना रेणुका जी के तहत रास्ते में गाड़ी खड़ी करने का विरोध करने और रास्ता मांगने पर एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। दबंगों ने युवक पर डंडों से इस कदर हमला किया कि उसके दाहिने हाथ की कलाई में गंभीर फ्रैक्चर हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार ददाहु तहसील के गांव बेडोन के निवासी विजेंद्र तोमर ने बताया कि बीते दिनों उनके घर में भतीजे की शादी का समारोह था। वह अपने पिता को छोड़ने के लिए अपने गांव से छोऊ भोगर जा रहे थे। जब वे रास्ते में थे, तो वहां लेखराज नामक व्यक्ति की गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी थी, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह बंद था। विजेंद्र तोमर ने जब लेखराज से अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड करने का आग्रह किया ताकि वे आगे निकल सकें, तो लेखराज अचानक आगबबूला हो गया। उसने बात मानने के बजाय तुरंत अपने भाई को मौके पर बुला लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर विजेंद्र तोमर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में विजेंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर गहरी चोट आई।

रोहडू में चरस के साथ दो काबू मारुति कार से हो रही थी तस्करी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिमला जिला के रोहडू क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो युवकों को 509 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। मामले में पुलिस थाना रोहडू में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार सोमवार की शाम डिटेक्शन सेल, उपमंडल रोहडू की टीम क्षेत्र में गश्त और अपराधों की रोकथाम के लिए मख्खीनाला रोहडू में मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि चिड़गांव की ओर से रोहडू आ रही एक मारुति 800 कार में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन को रोककर जांच की। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कार की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से 509 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय जितेन्द्र ठाकुर पुत्र हेत राम ठाकुर और 25 वर्षीय राजन ठाकुर पुत्र वीरेंद्र ठाकुर निवासी के रूप में हुई है। दोनों आरोपी शिमला के निवासी लोअर खलीनी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इस मामले में थाना रोहडू में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 25 और 29 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की जांच जारी है और दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।

कांग्रेस सरकार जाने वाली है, भाजपा सरकार आने वाली है: डॉ. बिन्दल

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिन्दल ने मंगलवार को जिला परिषद के त्रिलोकपुर वार्ड. न. 12 (काला आम) से भाजपा समर्थित प्रत्याशी प्रोमिला शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार हेतू आयोजित विभिन्न बैठकों और जन सम्पर्क के दौरान कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब जाने वाली है और प्रदेश में भाजपा सरकार आने वाली है।

उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक सफलता से स्पष्ट हो गया है कि व्यवस्था पतन की कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। डा. बिन्दल ने मोगीनन्द, नागल सुकेती, मैनथापल, त्रिलोकपुर, पालियों, कौलावाला भूड़, जंगला भूड, बर्मा पापडी और सलानी कटोला में आयोजित चुनाव जन सम्पर्क अभियान में भाग लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को जिला परिषद सहित पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में वोट मांगने का अधिकार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने साढ़े तीन साल में एक भी विकास का कार्य नहीं किया और भाजपा सरकार के समय खोले गए जनहित के दर्जनों संस्थानों को ताले जड़ दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल, स्वास्थ्य संस्थान, पटवार सर्कल, तहसील, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा जैसे 15 से अधिक जन हितैषी सस्थानों पर ताला जड़ने वाली कांग्रेस सरकार को इन चुनावा में जनता अच्छा सबक सिखयेगी।

चुनाव | हिमाचल में 131 ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं

10,854 प्रतिनिधि बिना मुकाबले बने विजेता

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बीच बड़ी संख्या में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में कुल 10,854 प्रतिनिधि बिना मुकाबले निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें 131 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, जहां प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। प्रदेश में कुल 3754 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश सरकार चुनाव से पहले निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा कर चुकी है।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि राज्यभर में 85 पंचायत समिति सदस्य, 176 प्रधान, 286 उपप्रधान और 10,307 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। इसके अलावा 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो बिलासपुर में 3 प्रधान, 2 उपप्रधान और 415 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि एक ग्राम पंचायत भी निर्विरोध रही है। चंबा में 4 पंचायत समिति सदस्य, 7 प्रधान, 7 उपप्रधान और 400 वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तथा एक पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। हमीरपुर में 3 पंचायत समिति सदस्य, 2 उपप्रधान और 582 वार्ड सदस्य बिना मुकाबले चुने गए हैं। आयोग के अनुसार कांगड़ा में 5 पंचायत समिति सदस्य, 10 प्रधान, 8 उपप्रधान और 1657 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि दो ग्राम पंचायतें निर्विरोध रहीं। किन्नौर में 7 पंचायत समिति सदस्य, 22 प्रधान, 23 उपप्रधान और 262 वार्ड सदस्य बिना मुकाबले निर्वाचित हुए हैं तथा यहां 18 ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं।

लाहौल-स्पीति में 3 पंचायत समिति सदस्य, 6 प्रधान, 18 उपप्रधान और 809 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं तथा 5 पंचायतें निर्विरोध रहीं। कुल्लू में 5 पंचायत समिति सदस्य, 9 प्रधान, 14 उपप्रधान और 1296 वार्ड सदस्य बिना मुकाबले चुने गए हैं, जबकि 5 ग्राम पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं।

मंडी में 12 पंचायत समिति सदस्य, 17 प्रधान, 20 उपप्रधान और 206 वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तथा 17 पंचायतें निर्विरोध रही हैं। शिमला में सबसे अधिक 21 पंचायत समिति सदस्य, 51 प्रधान, 87 उपप्रधान और 1687 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। यहां 42 ग्राम पंचायतें बिना मुकाबले निर्वाचित हुई हैं। सिरमौर में 18 पंचायत समिति सदस्य, 32 प्रधान, 71 उपप्रधान और 1166 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं तथा 22 ग्राम पंचायतें निर्विरोध रहीं। सोलन में 9 पंचायत समिति सदस्य, 14 प्रधान, 27 उपप्रधान और 1121 वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तथा 13 पंचायतें बिना मुकाबले चुनी गई हैं। ऊना में 2 पंचायत समिति सदस्य, 8 प्रधान, 7 उपप्रधान और 706 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि 5 ग्राम पंचायतें निर्विरोध रही हैं।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

नायब सैनी ने साइकिल से सफर कर दिया ईंधन बचत और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश

प्रधानमंत्री के ऊर्जा संरक्षण आान को जन अभियान बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार के ठोस कदम

सिटी दर्पण स ंवाददाता
चंडीगढ़

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और विकसित भारत के निर्माण को लेकर किए गए आान को जन अभियान का स्वरूप देने की दिशा में हरियाणा सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार सुबह साइकिल से सफर कर प्रदेशवासियों को ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री सुबह-सुबह चंडीगढ़ में सुखना लेक पहुंचे, जहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों से मुलाकात कर स्वस्थ भारत-स्वस्थ हरियाणा का आान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और मिडल ईस्ट में बने हालात के मद्देनजर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आमजन से पेट्रोल-डीजल की बचत करने, सुरक्षित यात्रा करने, इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करने तथा अनावश्यक ईंधन खपत कम करने का आान किया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी प्रधानमंत्री के इस आान को गंभीरता से लेते हुए राज्य स्तर पर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने, वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाने तथा सरकारी कार्यप्रणाली में ऊर्जा बचत को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से आमजन को भी इस मुहिम से जोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्ष से भी राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने में सहयोग देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब देशवासियों से सहयोग की अपील की थी, तब पूरे देश ने एकजुट होकर उसका पालन किया और सामूहिक प्रयासों से भारत उस संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकला। उसी प्रकार आज भी यदि सभी नागरिक ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को अपना दायित्व मानकर आगे आएंगे तो देश हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगा।

हरियाणा ने ईंधन संरक्षण के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू कर स्वच्छ गतिशीलता के लिए जारी किये दिशा-निर्देश

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेशभर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए ईंधन संरक्षण और ऊर्जा बचत के आह्वान पर कार्रवाई करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों तथा सरकारी विभागों से दैनिक सरकारी कार्यप्रणाली में ईंधन दक्षता संबंधी उपायों को सक्रिय रूप से अपनाने का आान किया है। हरियाणा के सभी उपायुक्तों को जारी पत्र में डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामूहिक राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे ऐसे व्यावहारिक एवं प्रभावी कदम अपनाएं, जिनसे ईंधन की खपत तथा कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सके। इस पहल के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यक्तिगत वाहनों के बजाय दैनिक आवागमन के लिए मेट्रो, बस एवं रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही, कारपूलिंग एवं राइड-शेयरिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ईंधन की बचत के साथ-साथ यातायात दबाव भी कम किया जा सके। विभागों को साझा यात्रा व्यवस्था के लिए डिजिटल समन्वय प्लेटफॉर्म एवं व्हाट्सऐप समूहों का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है।

सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 252 करोड़ की विभिन्न खरीदों को मंजूरी

सिटी दर्पण स ंवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार देर सायं हरियाणा निवास में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए लगभग 252 करोड़ रुपये की खरीद संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न कंपनियों के साथ नैगोशिएशन कर कई वस्तुओं की दरों में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित कर सरकारी धन के प्रभावी उपयोग पर बल दिया।

बैठक में हरियाणा पुलिस के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से 50 स्क्वेयर एमएम आकार के 18000 रैबिट कंडक्टर की खरीद को भी मंजूरी दी गई। साथ ही, एचवीपीएनएल के लिए लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से 5 प्रकार के 132/66 केवी सीआरएम पैनल्स की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग की साधारण बसों, एसी बसों, मिनी बसों तथा ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की बसों के दो वर्ष के बीमा संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने सरकारी बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को पिछले वर्ष की दरों पर ही बीमा करने के लिए सहमत करवाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पैसा जनता का पैसा है और सरकार केवल इसकी कस्टोडियन है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन के व्यय में पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा प्रत्येक विभाग को खरीद प्रक्रिया में बाजार दरों, पिछले वर्षों की दरों और अन्य राज्यों में प्रचलित दरों का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ताकि सरकारी धन का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा, महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, एडीजीपी एएस ढिल्लों, ऊर्जा विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, एचवीपीएन के एमडी आदित्य दहिया तथा डीएचबीवीएन के एमडी श्री विक्रम सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सैनी ने तालाबों के प्रबंधन व रख-रखाव को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

सिटी दर्पण स ंवाददाता
चंडीगढ़

- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने की हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में तालाबों के प्रबंधन एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनमें गंदा पानी न पहुंचे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों की नियमित सफाई करवाई जाए तथा इस कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में जोहड़ आबादी के बीच आ गए हैं, वहां उनकी सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने तालाबों के किनारों को मजबूत करने, गाद निकालने और किनारों पर उगी घास की सफाई करवाने के निर्देश दिए। साथ ही तालाबों के आसपास लोगों के सैर के लिए पक्की पगडंडी, बैठने के लिए बेंच तथा सोलर लाइट लगाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि तालाबों के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण करने तथा किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसे तत्काल दूर करवाने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि गांवों के गंदे पानी को सीधे तालाबों में न डाला जाए। इसके लिए थ्री-पॉन्ड सिस्टम विकसित किया जाए ताकि पानी को साफ करने के बाद ही तालाबों में छोड़ा जाए।

सुपवा में सिखा रहे फिल्मों के सेट बनाने का हुनर

सिटी दर्पण स ंवाददाता
रोहतक

दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) के छात्र इन दिनों फिल्मों के सेट तैयार करने की विधा सीख रहे हैं। इसके लिए बॉलीवुड के प्रॉडक्शन डिजाइनर राहुल बाला सुपवा आए हैं, जो फिल्म एवं टेलीविजन फैकेल्टी के छात्रों की वर्कशॉप ले रहे हैं। वर्कशॉप के दौरान वे सेट तैयार करने के दौरान ध्यान रखी जाने वाली बारीरियों से छात्रों को अवगत करा रहे हैं।

फिल्म एवं टेलीविजन फैकेल्टी के एफसी महेश टीपी बताते हैं कि राहुल बाला एफटीआईआई, पुणे और कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली से फोटोग्राफी व प्रॉडक्शन डिजाइन में प्रशिक्षित हैं। वे सोहम शाह फिल्म्स की चमकीला, स्टेज ओटीटी की वेब सीरीज अखाड़ा, इम्तियाज अली द्वारा प्रस्तुत और जीना अभी बाकी है, में प्रॉडक्शन डिजाइनर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। बच्चों की शॉर्ट फिल्म दूरबीन का सह-निर्माण और शूट भी उन्होंने ही किया था, जिसने एनडीएफएफ 2021 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार हासिल किया था। कुलगुरु डॉ अमित आर्य ने कहा कि फिल्मों में दिखने वाली भव्यता सिर्फ कलाकारों या लोकेशन की देन नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक पूरी टीम की महीनों की मेहनत छिपी होती है। जब भी आप किसी ऐतिहासिक या भव्य फिल्म को देखते हैं तो उसके सेट आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन यह जादू अचानक नहीं बनता, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित और बेहद तकनीकी प्रक्रिया होती है।

बॉलीवुड के प्रॉडक्शन डिजाइनर राहुल बाला ने छात्रों को बताया कि फिल्म का सेट तैयार करने की जिम्मेदारी प्रॉडक्शन डिजाइनर व आर्ट डायरेक्टर की होती है। ये लोग निर्देशक के विजन को समझकर पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। इसमें हर छोटी-बड़ी डिटेल शामिल होती है, जैसे महल का आकार, दरवाजों की डिजाइन, रंगों का संयोजन और यहां तक कि दीवारों की बनावट कैसी रहेगी। इसके बाद लकड़ी, फाइबर, प्लास्टर और अन्य विशेष सामग्री की मदद से सेट को धीरे-धीरे खड़ा किया जाता है। कई बार सेट इतने वास्तविक बनाए जाते हैं कि दर्शक उन्हें असली लोकेशन समझ बैठते हैं। उन्होंने कहा कि सिनेमा एक विजुअल आर्ट है, जहां हर फ्रेम को खास बनाने के लिए बारीकी से काम किया जाता है। यही वजह है कि जब दर्शक इन सेट में शूट हुई फिल्मों को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि एक भव्य अनुभव भी मिलता है जो लंबे समय तक याद रहता है।

संक्षिप्त-समाचार

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

चंडीगढ़। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष-2026 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य उन बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना है, जिन्होंने कम उम्र में विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं और समाज के लिए प्रेरणा बने हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि इस पुरस्कार के लिए छह प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इस पुरस्कार के लिए वे सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हो और जो 31 जुलाई,2026 तक 18 वर्ष से कम आयु के हों। नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई,2026 निर्धारित की गई है।

हरियाणा ने टीबी मुक्त भारत अभियान को दी रफ्तार : डॉ. मनीष बंसल

चंडीगढ़। देश को तपेदिक (टीबी) से मुक्त करने के संकल्प को और मजबूत करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल और मिशन चेतना फाउंडेशन प्रमुख सुश्री मनीषा चौधरी ने आज पंचकुला से बाल टीबी मरीजों के लिए विशेष, फोर्टिफाइड पोषण आहार पैकेट ले जा रहे एक समर्पित वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण वितरण का यह महत्वपूर्ण अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 'निक्षय मित्र' पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है। मिशन चेतना फाउंडेशन और राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया ने निक्षय मित्र के रूप में आगे आते हुए हरियाणा राज्य के तीन जिलो में 70 बाल टीबी मरीजों (उम्र 0-18 वर्ष) को 6 महीने की अवधि के लिए गोद लिया है जिसमे पंचकुला के 20, अंबाला के 20 और यमुनानगर के 30 मरीज हैं। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. मनीष बंसल ने कहा कि टीबी के सफल इलाज के लिए पर्याप्त पोषण बेहद बुनियादी जरूरत है। ₹टीबी के इलाज के लिए मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को बढ़ाना और दवाइयों का नियमित सेवन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इन युवा मरीजों के दैनिक आहार में वैज्ञानिक रूप से तैयार, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को शामिल करके, हम इलाज बीच में छोड़ने की दर (डिफॉल्ट रेट) को कम कर रहे हैं और मरीजों के तेजी से ठीक होने का रास्ता साफ कर रहे हैं। उन्होंने आम नागरिकों से इस 'जनभागीदारी' आंदोलन से जुड़ने और टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की है। कार्यक्रम में राज्य टीबी अधिकारी डॉ. राजेश राजू, निक्षय मित्र पहल की राज्य कार्यक्रम अधिकारी सुश्री प्रिया जायसवाल, स्टेट टीबी सेल के अधिकारी व कर्मचारी और एनजीओ के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सेना भर्ती कार्यालय, हिसार द्वारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 की तिथियां घोषित

चंडीगढ़। भारतीय सेना में भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा 1 जून से 12 जून 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इस बारे जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय हिसार के प्रवक्ता ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 15 मई 2026 को भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट ६६६.ZZल्ल्लल्लिं१८.ल्लू.ल्ल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एडमिट कार्ड पर उपलब्ध कराई गई है। प्रवक्ता ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पूर्ण रूप से पालन करें। परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम तथा गेट बंद होने का समय भी एडमिट कार्ड पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है, इसलिए अभ्यर्थी समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

भाजपा सरकार देश की परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल: सैलजा

सिटी दर्पण स ंवाददाता
सिरसा

सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय और भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हुए कहा कि नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार देश की परीक्षा व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल रही है। वे मंगलवार को सिरसा में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। सांसद ने भाजपा सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय और भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार देश की परीक्षा व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह विफल रही है। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी लगातार जिस खतरे की ओर देश का ध्यान दिलाते रहे हैं, आज वही स्थिति पूरे देश में दिखाई दे रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा। हर बार छोटे स्तर पर कार्रवाई दिखाकर सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हो, तब जवाबदेही शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि देश का युवा मेहनत कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार व्यवस्था सुधारने के बजाय अपनी विफलताओं को छुपाने में लगी है।

सांसद ने सरकार से मांग की कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाए। इस अवसर पर कालांवाली के विधायक शीशपाल कहरवाला, जिला अध्यक्ष संतोष बैनीवाल, महिला जिला कांग्रेस की अध्यक्ष कृष्णा फोगाट, वीरभान मेहता, राजेश चांडीवाल, संदीप नेहरा, राजकुमार शर्मा, नवीन केडिया, इंद्र जैन कालांवाली, रणधीर सिंह, सुरजीत सिंह भावदीन आदि मौजूद थे।

अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन मामलों का होगा समय पर निपटान

सिटी दर्पण स ंवाददाता
चंडीगढ़

- हरियाणा सरकार ने किया एलपीसी प्रारूप में संशोधन
- विभागों को संशोधित प्रारूप में ही जारी करना होगा लास्ट पे सर्टिफिकेट

हरियाणा सरकार ने आईएएस और एचसीएस अधिकारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन तथा पेंशन मामलों का समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) के प्रारूप में संशोधन किया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि देखने में आया है कि आईएएस एवं एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति के समय संबंधित विभागों से सेवा सत्यापन, अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान से संबंधित चालान समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण पेंशन मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी होती है।

इसे देखते हुए वित्त विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के तहत पंजाब ट्रेजरी नियमावली, भाग-दो में परिभाषित एलपीसी प्रारूप में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब हर विभाग को अधिकारी के स्थानांतरण अथवा कार्यमुक्त होने के समय ही सेवा को प्रमाणित करना अनिवार्य होगा, ताकि सर्विस रिकॉर्ड का निरंतर एवं समकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

निर्देशों के अनुसार अब सभी एलपीसी केवल संशोधित प्रारूप में ही जारी किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में क्रम संख्या-10 पर सेवा सत्यापन का विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त, आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के संबंध में जारी प्रत्येक एलपीसी की प्रति मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विसेज ब्रांच-4 को भी भेजी जाएगी, ताकि सर्विस रिकॉर्ड का उचित रखरखाव किया जा सके तथा पेंशन एवं सेवानिवृत्ति मामलों का निपटान समय पर हो सके। बोर्डों एवं निगमों में कार्यरत आईएएस एवं एचसीएस अधिकारियों से संबंधित अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान के चालान भी मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार ने घटते लिंगानुपात को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों पर की सख्त कार्रवाई

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- प्रभावी मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर चार वरिष्ठ डॉक्टर निलंबित, विभागीय कार्रवाई के दिए आदेश

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में घटते लिंगानुपात को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्यसचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने लिंगानुपात सुधार से जुड़े उपायों की प्रभावी मॉनिटरिंग, क्रियान्वयन में कथित लापरवाही तथा खराब प्रदर्शन के आरोप में चार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध लिंग जांच, कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा प्रदेश में लैंगिक संतुलन मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उसमें जिला सोनीपत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरखास में तैनात एसएमओ डॉ. टीना आनंद, यमुनानगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रादौर में तैनात एसएमओ डॉ. विजय परमार, रोहतक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिड़ी में तैनात एसएमओ डॉ. सतपाल तथा नारनौल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सहलांग में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभा शामिल हैं। निलंबन अवधि के दौरान इन सभी अधिकारियों को क्रमशः रोहतक, अंबाला, झज्जर और रेवाड़ी के सिविल सर्जन कार्यालयों से संबद्ध किया गया है। सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिंगानुपात सुधार से संबंधित उपायों की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में विफलता तथा खराब प्रदर्शन के चलते यह सख्त कार्रवाई की गई है।

यमुना में गिरने वाले नालों की मैपिंग के लिए होगा जोन-वाइज ड्रोन सर्वे

सिटी दर्पण स ंवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में गिरने वाले सभी प्रमुख और छोटे नालों की मैपिंग के लिए जोन-वाइज ड्रोन सर्वेक्षण करवाया जाएगा। इसके माध्यम से जल प्रवाह और जल गुणवत्ता, दोनों की निगरानी की जाएगी। यह पहल दिल्ली में किए जा रहे सर्वेक्षणों की तर्ज पर प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान और स्रोत स्तर पर निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।

गौरतलब है कि हरियाणा ने यमुना नदी के पुनरुद्धार तथा अंतरराज्यीय नालों के माध्यम से दिल्ली में पहुंचने वाले प्रदूषित जल को रोकने की दिशा में व्यापक कार्ययोजना लागू की है। इस योजना के तहत सीवेज उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और नालों की रियल-टाइम निगरानी पर खास जोर दिया जा रहा है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने आज यहां राज्य की व्यापक प्रदूषण नियंत्रण रणनीति की समीक्षा की, जिसका उद्देश्य हरियाणा के नालों से यमुना नदी प्रणाली के माध्यम से दिल्ली में प्रवेश करने वाले प्रदूषित जल को रोकना है। बैठक में सीवेज उपचार अवसंरचना को मजबूत करने, बायो कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के स्तर को कम करने तथा औद्योगिक अपशिष्ट के सख्त निरीक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में राज्य को जारी निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा भी की गई। साथ ही हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले अंतरराज्यीय नालों- ड्रेन नंबर-6, मुंगेशपुर ड्रेन, बुपनिया ड्रेन और पालम विहार ड्रेन आदि के प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर भी चर्चा की गई।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 34 शहरों में 1,518 एमएलडी क्षमता वाले 90 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 170 एमएलडी क्षमता वाले 4 नए एसटीपी निमार्णाधीन हैं, जबकि 227 एमएलडी क्षमता के 9 एसटीपी को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि उपचार क्षमता और दक्षता को बढ़ाया जा सके।

औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य में 184.5 एमएलडी क्षमता वाले 17 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) कार्यरत हैं।

इनमें से 19 एमएलडी क्षमता वाले 2 सीईटीपी को अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली को और मजबूत करने के मकसद से 146 एमएलडी क्षमता वाले 8 नए सीईटीपी प्रस्तावित हैं।

अधिकारियों ने बताया कि भविष्य की विस्तार योजना के तहत प्रदेश में 510 एमएलडी क्षमता वाले 9 नए एसटीपी स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एसटीपी, सीईटीपी और ड्रेन टैपिंग परियोजनाओं को मिलाकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।

कई परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो चुका है और इन्हें दिसंबर 2028 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

राज्य सरकार ने यमुना एक्शन प्लान-2019 के तहत जल गुणवत्ता सुधार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं।

हरियाणा का लक्ष्य यमुना नदी में ह्यबी-क्लासह्ण जल गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना है, जिसमें बीओडी स्तर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे कम, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन स्तर कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर तथा कोलीफॉर्म स्तर निर्धारित मानकों के भीतर रखना शामिल है। इसके लिए नियमित निगरानी और समीक्षा तंत्र विकसित किया जा रहा है।

बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री योगेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलनः उत्तरी यूरोप के साथ एक नई रणनीतिक सुबह

19 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ एक ही मंच पर बैठे, तो यह दृश्य केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं था – यह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का एक सशक्त और ऐतिहासिक प्रतीक था। तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब केवल एशिया की एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि यूरोप के साथ भी एक विश्वसनीय, महत्त्वाकांक्षी और दूरदर्शी साझेदार के रूप में स्थापित हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन इस अर्थ में भी ऐतिहासिक है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा 43 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी नॉर्वे आई थीं। इस तथ्य को देखते हुए मोदी की यह यात्रा न केवल भारतीय प्रवासियों के लिए, बल्कि नॉर्वे की पूरी कारोबारी और राजनीतिक बिरादरी के लिए उत्साह और उम्मीदों का नया अध्याय लेकर आई। ओस्लो हवाई अड्डे पर नॉर्वेजियन प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने स्वयं मोदी की अगवानी की, जो इस संबंध की गर्मजोशी और महत्त्व को रेखांकित करता है। इस पूरी यात्रा की पृष्ठभूमि में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की जटिलताएँ हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध अभी थमा नहीं है। अमेरिका के व्यापक आयात शुल्कों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्थिर कर दिया है। मार्च 2026 में होर्मुज जलडमरूमध्य के संकट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया, क्योंकि भारत के अधिकांश एलएनजी और एलपीजी आयात विदेशी जहाजों पर निर्भर हैं। इन चुनौतियों के बीच भारत के लिए अपनी आर्थिक और ऊर्जा साझेदारियों का विस्तार करना और विविधीकरण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। नॉर्डिक देश इस दिशा में भारत के सबसे स्वाभाविक और भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरे हैं। शिखर सम्मेलन का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि भारत और नॉर्डिक देशों ने अपने संबंधों को 'विश्वसनीय हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी' के रूप में उन्नत करने पर सहमति जताई। यह उन्नयन केवल नामकरण की औपचारिकता नहीं है – इसके पीछे एक ठोस कार्यसूची है जो प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास, नीली अर्थव्यवस्था, रक्षा, अंतरिक्ष और आर्कटिक सहयोग जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को समेटती है। नॉर्डिक देश इन सभी क्षेत्रों में विश्व के अग्रणी हैं और भारत की विकास प्राथमिकताओं के साथ इनका तालमेल स्वाभाविक और फलदायी है। द्विपक्षीय स्तर पर भी इस यात्रा के उल्लेखनीय परिणाम रहे। नॉर्वे के साथ भारत ने 'हरित रणनीतिक साझेदारी' स्थापित की और मोदी ने नॉर्वे को भारत की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश का आमंत्रण दिया। स्वीडन के साथ 'रणनीतिक साझेदारी' की घोषणा हुई, 'संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0' और 'भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर' लॉन्च किए गए, और पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। फिनलैंड के साथ व्यापार, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित परिवर्तन में सहयोग गहरा करने पर सहमति बनी, जबकि आइसलैंड के साथ स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और आर्कटिक सहयोग पर चर्चा हुई। व्यापार की दृष्टि से यह साझेदारी पहले से ही मजबूत आधार पर खड़ी है। 2024 में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच कुल व्यापार 19 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फिनलैंड की नोकिया, स्वीडन की वॉल्वो और आईकेईए जैसी कंपनियाँ भारतीय बाजार में लंबे समय से सक्रिय हैं। भारतीय जहाज निर्माण कंपनियाँ नॉर्वेजियन शिपओनर्स एसोसिएशन के ऑर्डर बुक में 11 प्रतिशत की भागीदारी रखती हैं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के साथ भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौता किया है, जिसकी अनुमानित लागत 2,329 करोड़ रुपये है और इसकी डिलीवरी 2029-30 तक अपेक्षित है। यह सहयोग भारत की समुद्री शक्ति और ध्रुवीय अनुसंधान क्षमता को नई ऊँचाई देगा। इस शिखर सम्मेलन का एक अत्यंत दूरदर्शी पहलू है – आर्कटिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती सक्रियता। यद्यपि भारत की किसी आर्कटिक देश के साथ कोई भूमि या समुद्री सीमा नहीं है, परंतु 1920 की स्वालबार्ड संधि के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक हितधारक है। आर्कटिक आज केवल बर्फ और ध्रुवीय भालुओं की भूमि नहीं रही – यह 21वीं सदी का एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक केंद्र बनता जा रहा है। नॉर्डिक देशों की हिम-श्रेणी जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, ध्रुवीय अनुसंधान और खनिज निष्कर्षण में विशेषज्ञता भारत के लिए अमूल्य है। ग्रीनलैंड के दुर्लभ खनिज भंडार, फिनलैंड की आइसब्रेकर तकनीक, आइसलैंड की आर्कटिक विज्ञान पहलें और नॉर्वे की समुद्री शासन विशेषज्ञता – ये सभी भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मोर्चे पर भी शिखर सम्मेलन ने सकारात्मक संदेश दिया। नॉर्डिक देशों ने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। हरित हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर एवं उपयोग, शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों में सहयोग तेज करने पर सहमति बनी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी नेताओं ने समावेशी, लोकतांत्रिक और अधिकार-आधारित वैश्विक एआई प्रशासन की दिशा में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत के फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' की भी नेताओं ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। अगला, चौथा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन फिनलैंड में आयोजित करने का निर्णय भी इस यात्रा की एक सुखद उपलब्धि है। मोदी की यह यात्रा उनके पाँच देशों के व्यापक यूरोप दौरे का हिस्सा है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। नीदरलैंड्स में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच अर्धचालक दिग्गज एएसएमएल के बीच हुआ सहयोग समझौता भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक मील का पत्थर है। इस पूरे दौरे में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की सक्रिय उपस्थिति ने यात्रा की रणनीतिक गंभीरता और तैयारी की गहराई को दशार्या। संक्षेप में, ओस्लो का यह शिखर सम्मेलन भारत की उस महत्त्वाकांक्षी वैश्विक दृष्टि का प्रकटीकरण है जो उसे एक बहुध्रुवीय विश्व में एक केंद्रीय और विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है। नॉर्डिक देशों की तकनीकी श्रेष्ठता और भारत की विशाल बाजार क्षमता एवं मानव पूँजी का यह संगम न केवल दोनों पक्षों के लिए, बल्कि एक अस्थिर विश्व में स्थिरता और सहयोग की तलाश करने वाले सभी देशों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। भारत-नॉर्डिक साझेदारी की यह नई सुबह उज्ज्वल है, संभावनाओं से भरपूर है और आने वाले दशकों के लिए एक मजबूत नींव रखती है।

उर्वरक उपयोग में कमी से आएगा व्यापक बदलाव

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (हि.स)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले दिनों देशवासियों से किये गए सात आग्रहों में से एक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक कमी लाने का है। इसमें दो राय नहीं कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुध उपयोग के दुष्परिणामों को लेकर गत कई सालों से गंभीर आग्रह किये जा रहे हैं। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन सेचुरेशन स्तर पर पहुंच गया है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंच रहा है, मिट्टी और जल प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंच गया है तो रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कैंसर जैसी बीमारियों का दायरा बहुत अधिक बढ़ गया है। यहां तक कि अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन वाले किसान और प्रदेश अपने दैनिक उपभोग के लिए जैविक खाद्यान्न या अन्य प्रदेशों के खाद्यान्न के उपयोग पर जोर देने लगे हैं। यह भी तथ्य है कि देश में लाख प्रयासों के बावजूद रासायनिक उर्वरकों का आयात लगातार बढ़ रहा है। विदेशों से 979 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात में से ईंधन के बाद बहुत अधिक आयात राशि उर्वरकों पर भी व्यय होती है।

देश में करीब 600 लाख टन उर्वरकों की खपत है जिसके साल 2030 तक 700 से 800 लाख टन तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तस्वीर का एक पक्ष यह है कि रासायनिक उर्वरकों में देश की मांग के शत-प्रतिशत पोटाश की विदेशों से आयात पर निर्भरता है तो फास्फेट के तकरीबन 90 प्रतिशत और यूरिया के करीब 25 प्रतिशत तक आयात पर निर्भरता है। यूरिया की आयात निर्भरता करीब 25 प्रतिशत तक है पर यूरिया उत्पादन के लिए काम में आने वाली प्राकृतिक गैस की जरुरत करीब 80 प्रतिशत तक विदेशों से आयात से ही संभव हो पाती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार रासायनिक उर्वरकों पर दो लाख करोड़ के आसपास अनुदान राशि दी जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत तक कटौती का आग्रह किया है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने के लिए जहां एक और जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है वहीं पीएम प्रणाम योजना में राज्यों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री का आग्रह है कि 10 प्रतिशत फर्मेंटेड खाद का उपयोग बढ़ाकर किसान बड़ा सहयोग दे सकते हैं। जून 2023 में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना के अनुसार रासायनिक उर्वरकों के तीन साल के औसत उपयोग से खपत कम करने पर अनुदान के रुप में बचाई गई राशि की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को प्रोत्साहन के रुप में देने की व्यवस्था की गई है। इसमें से 70 प्रतिशत राशि गांवों में वैकल्पिक उर्वरक यानी जैविक खाद उत्पादन व तकनीक के विस्तार पर व्यय करने पर जोर दिया जा रहा है वहीं, 30 प्रतिशत राशि रासायनिक उर्वरकों की खपत करने के लिए काश्तकारों को जागरुक करने, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने आदि पर व्यय करने का प्रावधान है।

विशेषज्ञों का मानना है कि फर्मेंटेड खाद के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में अच्छी खासा कमी लाई जा सकती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फर्मेंटेड खाद मिलाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री बीजेयूआर कार्यक्रम के तहत मिट्टी की जांच का जो व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य भी यही है कि खेत की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग किया जाए। अंधाधुंध उपयोग रोक कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखना है।

यह सबके संज्ञान में है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्रभावित हो रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन होने से भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, वहीं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के कारण खतरनाक स्तर पर प्रदूषित हो रहा है। जैविक विविधता प्रभावित हो रही है तो खेती के सहायक कीटनाशकों का अस्तित्व ही समाप्त होने को है। इसके अलावा खाद्यान्नों के विषैला होने व इन खाद्यान्नों के उपयोग से बीमारियों का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इतना सबकुछ होने के बावजूद रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। साल 2025-26 के आंकड़ों की ही बात करें तो यूरिया में 138 प्रतिशत, डीएपी के उपयोग में 94 प्रतिशत और एनपीके के उपयोग में 83 प्रतिशत के आसपास बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आग्रह के निहितार्थ को समझना होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आग्रह इस मायने में बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि सरकार देश की जरुरतों को पूरा नहीं कर पा रही। अपितु गंभीर चिंतन की बात यह है कि हम परंपरागत खेती या जैविक खेती को बढ़ावा देकर आने वाली पीढ़ी और जल-मिट्टी, वायु के प्रदूषण को कम करने में भागीदार बन सकते हैं। केवल 10 प्रतिशत फर्मेंटेड खाद मिलाने से ही बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। 50 प्रतिशत तक आयात निर्भरता कम की जा सकती है। आज हम रुस, ओमान, सउदी अरब, मोरक्को, चीन आदि पर उर्वरकों के आयात के लिए निर्भर हैं। अरबों डालर आयात पर खर्च करके भी इसके जरिये हमें प्रदूषण और सेहत से खिलवाड़ मिल रहा है।

हालांकि आज अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आसन्न संकट को देखते हुए दूरदृष्टि पूर्ण 7 आग्रहों को प्रतिपक्ष आलोचना के स्तर पर ले रहा है पर यह नहीं भूलना चाहिए कि पीएम प्रणाम कार्यक्रम जून 23 से चलाया जा रहा है तो पीएमबीजेयूआर कार्यक्रम जो कि खेत की मिट्टी की जांच से जुड़ा कार्यक्रम है, वह वर्षो से जारी है। इसके साथ ही आज कृषि वैज्ञानिक बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग घातक स्तर पर पहुंच रहा है।

पंजाब और उससे सटते इलाकों में खेती के हालात बयां कर रहे हैं। ऐसे में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50 प्रतिशत कमी के आग्रह को सकारात्मक लिया जाना चाहिए। इस बहाने हमें खेती को सही दिशा देने का अवसर मिला है। खरीफ की बुवाई में ही इस पर अमल किया जा सकता है। खेती और पर्यावरण से जुड़े सरकारी और गैरसरकारी संस्थाओं को प्रोएक्टिव रोल अपनाते हुए आगे आना होगा। यह एक अवसर मिला है और इस अवसर का सकारात्मक उपयोग को देश की खेती किसानी को नई दिशा दी जा सकती है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेषः मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। *(सिटी दर्पण)*

वृषभः समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है। अपने हितैषी समझे जाने वाले ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। *(सिटी दर्पण)*

मिथुनः हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात दूर हो जाएगी। अपने काम आसानी से बनते चले जाएंगे। साथ ही आगे के लिए रास्ता भी बन जाएगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग। जीवन साथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। *(सिटी दर्पण)*

कर्कः कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। कार्यक्षेत्र में आगे बढने में रुकावट का एहसास होगा। विरोधियों के सक्रिय होने की संभावना है। शुभकार्यों में अड़चनें व परिवार के बुजुर्ग-जनों से मतभेद रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

सिंहः मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश सफल होगी। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। यात्रा शुभ रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

कन्याः अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। कारोबारी काम में बाधा उभरने से मानसिक अशांति बनी रहेगी। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बन जाएगी। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। *(सिटी दर्पण)*

तुलाः अपने काम पर नजर रखिए। स्वास्थ्य लाभ में समय और धन व्यय होगा। लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं। मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिकः पर-प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। आलस्य का त्याग करें। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। *(सिटी दर्पण)*

धनुः कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। मित्रों से सावधान रहें तो ज्यादा उत्तम है। *(सिटी दर्पण)*

मकरः आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक विवाद टालें। व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। निष्ठा से किया गया कार्य पराक्रम व आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। संतान-स्त्री पक्ष से लाभ होगा। *(सिटी दर्पण)*

कुंभः खान-पान में सावधानी रखें। व्यापार में प्रगति होगी। अपने अधीनस्त लोगों से कम सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। आय के योग बनेंगे। यात्रा का योग है। *(सिटी दर्पण)*

मीनः जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करें। आलस्य का त्याग करें। पुरुषार्थ का सहारा लें। कार्यसिद्धि होने में देर नहीं लगेगी। आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर वार्ता होगी। *(सिटी दर्पण)*

इटली और भारतः इंडो-भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लिए एक रणनीतिक साझेदारी

नरेंद्र मोदी

जॉर्जिया मेलोनी

भारत और इटली के संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। यह संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। यह संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहा है, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है।

हमारा सहयोग इस साझा समझ को दशार्ता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा तथा विविध बनाने का संकल्प लिया है, ताकि नए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। हम इटली की डिजाइन क्षमता, बेहतरीन विनिर्माण कौशल और विश्वस्तरीय सुपरकंप्यूटर तकनीक—जो उसे एक औद्योगिक महाशक्ति बनाती है—को भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, बड़े पैमाने की क्षमता, नवाचार और 100 से अधिक यूनिकॉर्न तथा 2 लाख स्टार्ट-अप वाले उद्यमी इकोसिस्टम के साथ जोड़कर एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं। यह केवल दो व्यवस्थाओं का साधारण मेल नहीं है, बल्कि ऐसा साझा मूल्य निर्माण है जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक ताकतें एक-दूसरे को और अधिक मजबूत बनाती हैं।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पुर्जे, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि-खाद्य क्षेत्र और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। 'मेड इन इटली' हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है, और आज इसका स्वाभाविक तालमेल 'मेक इन इंडियापहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ दिखाई देता है। इसी संदर्भ में, भारत के लिए उत्पादन में इतालवी कंपनियों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी – जो अब दोनों पक्षों से मिलाकर 1000 से अधिक हो चुकी है – एक सकारात्मक संकेत है। यह हमारी सप्लाई चेन के एकीकरण को और मजबूत करेगी।

तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया एक बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या, तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता—इन क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती है। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच बढ़ती साझेदारी भी इसे मजबूती देगी।

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों, के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इटली और भारत लंबे समय से इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं, ताकि एआई का विकास जिम्मेदार और मानव-केंद्रित हो।

भारत और इटली एआई को समावेशी विकास का एक शक्तिशाली माध्यम भी मानते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान, बहुभाषी तकनीकों के जरिए एआई सामाजिक और डिजिटल खाइयों को कम कर सकता है, न कि उन्हें और बढ़ा सकता भारत के मानव विजन-यानी तकनीक के केंद्र में मानव को रखने की सोच और इटली की मानव-केंद्रित 'एल्गोर-एथिक्स' की अवधारणा, जो उसकी मानवतावादी परंपरा पर आधारित है, पर आगे बढ़ते हुए, हमारी साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बने।

हमारा दृष्टिकोण भारत की विशाल डिजिटल क्षमता को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, ताकि तकनीक मानव गरिमा की सेवा कर सके।

सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करके, हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश एआई का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। यही सोच इटली की जी7 अध्यक्षता और 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के निष्कर्षों का मुख्य आधार है। एआई को इंसानों की ओर से इंसानों के लिए बनाई गई तकनीक मानने का अर्थ है यह स्पष्ट करना कि तकनीक न तो मनुष्य की जगह ले सकती है और न ही उसके मूल अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसका उपयोग जनमत को प्रभावित करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए भी नहीं होना चाहिए।

आज की तेजी से जुड़ी हुई दुनिया में स्वतंत्रता और मानव गरिमा की रक्षा का हमारा दृष्टिकोण इसी चुनौती पर आधारित है।

हमारा सहयोग अंतरिक्ष क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। अंतरिक्ष अनुसंधान और सैटेलाइट तकनीक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति तथा इटली की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता, संयुक्त परियोजनाओं और नई पीढ़ी की तकनीकों के विकास के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।

राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और स्थिरता बेहद आवश्यक हैं। इसलिए इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीकों जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सहयोग महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी चुनौतियों के खिलाफ मजबूती बढ़ाने में मदद करेगा।

ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण आधार है। दुनिया में ऊर्जा के विविध स्रोतों की ओर बढ़ रहे बदलाव के लिए नवाचार, निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। भारत और इटली नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन तकनीक, तथा स्मार्ट ग्रिड से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की पहल अपार संभावनाएं रखती है। यह इटली की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में उन्नत तकनीक और यूरोप के लिए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में उसकी रणनीतिक भूमिका के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इस संदर्भ में भारत की अगुवाई वाली प्रमुख पहलों- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) में अन्य देशों के साथ हमारा सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण है।

भौतिक, डिजिटल और मानवीय संपर्क ही वह कड़ी है जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है। भारत और इटली दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों-इंडो-पैसिफिक और भूमध्यसागर के केंद्र में स्थित हैं। अब इन क्षेत्रों को अलग-अलग नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, हम एक नए 'इंडो-मैडिटेरेनियन' क्षेत्र के उभरने को देख रहे हैं, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक महत्वपूर्ण गलियारा बन रहा है और हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है। इसी आपस में जुड़े हुए क्षेत्र में हमारा संबंध स्वाभाविक रूप से एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित होता है- ऐसी साझेदारी, जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है और नई वैश्विक परिस्थितियों को आकार देती है।

इस संदर्भ में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) एक ऐसी दूरदर्शी योजना है, जिसका उद्देश्य आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों और मजबूत सप्लाई चेन के माध्यम से हमारे क्षेत्रों को जोड़ना है। भारत और इटली अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

हम अपने साझा चुनौतियों का समाधान दोनों देशों के गहरे संबंधों और लंबे सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में 'धर्म' का विचार उस जिम्मेदारी की भावना को दशार्ता है, जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वहीं 'वसुधैव कुटुंबकम्'- अर्थात 'पूरी दुनिया एक परिवार है' का सिद्धांत आज के आपस में जुड़े डिजिटल युग में और भी अधिक प्रासंगिक लगता है।

ये मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा से भी मेल खाते हैं, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण काल में हैं। यह परंपरा हर व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति की उस शक्ति पर जोर देती है, जो समाजों और लोगों को एकजुट कर सकती है। इसलिए हमारी साझा दृष्टि का उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखते हुए भारत-इटली साझेदारी को मजबूत, आधुनिक और भविष्य उन्मुख आधार प्रदान करना है।

कार पर सस्ता, शिक्षा ऋण पर ब्याज दर ज्यादा क्यों

डॉ. प्रियंका सौरभ (हि.स)

भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा को हमेशा राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। हम अक्सर कहते हैं कि युवा देश का भविष्य हैं, शिक्षा समाज की रीढ़ है और ज्ञान ही विकास का आधार है। लेकिन जब व्यवहारिक व्यवस्था को देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। विडंबना यह है कि आज भारत में कार खरीदना आसान हो रहा है लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगातार कठिन और महँगा होता जा रहा है। बैंक आपको नई कार खरीदने के लिए आकर्षक ब्याज दरों पर तुरंत ऋण देने को तैयार मिल जाएंगे, परंतु वही बैंक जब किसी विद्यार्थी को शिक्षा ऋण देते हैं तो ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, नियम कठोर हो जाते हैं और भविष्य को जोखिम मान लिया जाता है। यह स्थिति केवल बैंकिंग प्रणाली की तकनीकी समस्या नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी है।

आज भारत में उच्च शिक्षा का खर्च सामान्य परिवारों के सामर्थ्य से बाहर होता जा रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, निजी विश्वविद्यालयों की पढ़ाई या विदेश में शिक्षा–हर क्षेत्र में फीस लाखों में पहुँच चुकी है। मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों की बचत लगा देते हैं, गहने बेचते हैं, भविष्य निधि तोड़ते हैं, फिर भी शिक्षा ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। दुखद स्थिति यह है कि जिस शिक्षा से एक युवा का भविष्य बनना है, उसी पर सबसे अधिक ब्याज का बोझ लाद दिया जाता है। कार लोन की ब्याज दरें कई बार शिक्षा ऋण से कम होती हैं। अर्थात एक उपभोक्ता वस्तु खरीदना शिक्षा प्राप्त करने से सस्ता पड़ता है। यह केवल आर्थिक असंतुलन नहीं बल्कि सामाजिक सोच की भी त्रासदी है।

बैंकिंग व्यवस्था का तर्क यह होता है कि कार लोन सुरक्षित होता है क्योंकि वाहन बैंक के लिए गिरवी संपत्ति का काम करता है। यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति भुगतान न करे तो कार जब्त की जा सकती है। लेकिन शिक्षा ऋण में बैंक के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती। वहाँ केवल छात्र की योग्यता, उसकी डिग्री और उसका भविष्य होता है। इसलिए बैंक इसे जोखिमपूर्ण निवेश मानते हैं। यह तर्क बैंकिंग दृष्टि से भले सही प्रतीत हो लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यंत संकीर्ण है। किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा निवेश उसकी युवा पीढ़ी होती है। एक छात्र जब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता या प्रशासक बनता है तो उसका लाभ केवल व्यक्तिगत नहीं होता, पूरा समाज उससे लाभान्वित होता है। ऐसे में शिक्षा ऋण को केवल व्यापारिक उत्पाद की तरह देखना दूरदर्शिता नहीं कहलाएगा।

वर्तमान समय में शिक्षा ऋण केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि मानसिक दबाव का कारण भी बनता जा रहा है। लाखों विद्यार्थी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही ईएमआई और ब्याज की चिंता में घिर जाते हैं। नौकरी मिलने से पहले ही कर्ज का भय उन्हें परेशान करने लगता है। कई छात्र अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार करियर चुनने के बजाय केवल अधिक वेतन वाली नौकरियों की ओर इसलिए भागते हैं ताकि ऋण चुका सकें। परिणामस्वरूप शोध, अध्यापन, साहित्य, सामाजिक सेवा और कला जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं की संख्या घटती जा रही है। समाज धीरे-धीरे केवल वेतन आधारित सफलता का समर्थक बनता जा रहा है।

इस समस्या का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय मध्यम वर्ग पर पड़ता है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार महँगी शिक्षा का खर्च आसानी से उठा लेते हैं। गरीब वर्ग के लिए सरकार की कुछ योजनाएँ और छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं। लेकिन सबसे अधिक संघर्ष उस वर्ग को करना पड़ता है जो 'गरीब' की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी लाखों रुपये की फीस वहन करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे परिवारों के लिए शिक्षा ऋण मजबूरी बन जाता है। एक पिता पूरी जिंदगी की कमाई बेटे या बेटी की पढ़ाई में लगा देता है, इस उम्मीद के साथ कि शिक्षा भविष्य को सुरक्षित करेगी। लेकिन जब उसी शिक्षा पर भारी ब्याज लग जाता है, तो वह सपना धीरे-धीरे आर्थिक बोझ में बदलने लगता है।

आज भारत में शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ा है। सरकारी संस्थानों की सीमित सीटों के कारण लाखों छात्रों को निजी कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। वहाँ फीस इतनी अधिक होती है कि सामान्य परिवारों के लिए बिना ऋण के पढ़ाई संभव नहीं रह जाती। कई बार छात्र केवल फीस और ब्याज के कारण अपने सपनों के संस्थान छोड़ देते हैं। प्रतिभा आर्थिक क्षमता के सामने हार जाती है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज के लिए चिंताजनक है।

यह भी विचारणीय है कि आज के समय में शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगति का माध्यम नहीं रही बल्कि आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व की आवश्यकता बन चुकी है। बिना उच्च शिक्षा के बेहतर रोजगार प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में यदि शिक्षा ही महँगी और ऋण बोझिल होगा तो सामाजिक असमानता और बढ़ेगी। जो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वे आगे निकल जाएंगे, जबकि सीमित साधनों वाले प्रतिभाशाली छात्र पीछे छूटते चले जाएंगे। यह केवल व्यक्ति की हानि नहीं होगी बल्कि देश अपनी संभावित प्रतिभाओं को खो देगा।

भारत सरकार को इस दिशा में गंभीर और दीर्घकालिक कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले शिक्षा ऋण की ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि सरकार वाहन उद्योग, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक नीतियाँ बना सकती है तो शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र के लिए अलग वित्तीय नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती? शिक्षा ऋण पर ब्याज न्यूनतम होना चाहिए और पढ़ाई पूरी होने तक ब्याज स्थगन की व्यवस्था व्यापक स्तर पर लागू की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त रोजगार मिलने तक ऋण पुनर्भुगतान में लचीलापन होना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में कई छात्रों पर डिग्री पूरी होते ही ईएमआई का दबाव शुरू हो जाता है, जबकि नौकरी मिलने में समय लग सकता है। यह मानसिक तनाव युवाओं की ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करता है। यदि सरकार और बैंक छात्रों को कुछ वर्षों का व्यावहारिक समय दें तो वे अपने करियर को अधिक स्थिरता के साथ शुरू कर पाएंगे। शिक्षा ऋण के साथ करियर आधारित सहायता मॉडल भी विकसित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र शोध, अध्यापन, सामाजिक सेवा या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना चाहता है तो उसके ऋण में विशेष छूट दी जा सकती है। इससे समाज के आवश्यक लेकिन कम वेतन वाले क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली युवाओं का आकर्षण बना रहेगा।

दुनिया के कई विकसित देशों में शिक्षा को सामाजिक निवेश माना जाता है। वहाँ सरकारें छात्रों को कम ब्याज पर ऋण, छात्रवृत्ति और आय आधारित पुनर्भुगतान जैसी सुविधाएँ देती हैं। भारत में भी यदि हम 'विश्वगुरु' बनने की कल्पना करते हैं तो हमें युवाओं को कर्ज के भय से मुक्त करना होगा। केवल भाषणों और नारों से ज्ञान आधारित समाज नहीं बनता, उसके लिए व्यवहारिक आर्थिक समर्थन भी आवश्यक होता है।

यह सच है कि बैंकिंग व्यवस्था को भी अपने आर्थिक हित देखने होते हैं लेकिन शिक्षा को केवल लाभ-हानि के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। कार सड़क पर चलती है लेकिन शिक्षा समाज को आगे बढ़ाती है। वाहन सुविधा देता है लेकिन ज्ञान राष्ट्र का भविष्य गढ़ता है। यदि कार लोन सस्ता और शिक्षा ऋण महँगा है तो यह हमारी प्राथमिकताओं के असंतुलन का संकेत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को उपभोग नहीं, निवेश माना जाए। एक शिक्षित युवा केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह परिवार, समाज और राष्ट्र की दिशा भी बदल सकता है। इसलिए शिक्षा पर लगाया गया हर रुपया भविष्य की नींव होता है। सरकार, बैंकिंग संस्थानों और समाज- तीनों को मिलकर यह समझना होगा कि यदि प्रतिभा आर्थिक बोझ के नीचे दब गई, तो देश का विकास भी अधूरा रह जाएगा। जिस दिन भारत में शिक्षा ऋण को बोझ नहीं, अवसर की तरह देखा जाने लगेगा, उस दिन शायद किसी विद्यार्थी को अपने सपनों की कीमत भारी ब्याज में नहीं चुकानी पड़ेगी। तभी शिक्षा वास्तव में अधिकार बनेगी, सुविधा नहीं।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

तारों और खंभों से मुक्त गांवों वाला देश का पहला राज्य बनेगा पंजाब, सतौज मॉडल पूरे देश को राह दिखाएगा: मान

भगवंत मान सरकार की ओर से गांव सतौज से बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने के प्रोजेक्ट की शुरूआत, गांवों को खंभों से मुक्त करने से पंजाब के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी

सिटी दर्पण संवाददाता
संगरूर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब को देश का पहला खंभा-मुक्त गांवों वाला राज्य बनाने के लिए आज अपने पैतृक गांव सतौज में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड (जमीनदोज) करने के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करके अपनी तरह की अनूठी और ऐतिहासिक पहल की शुरूआत की। किसानों और गांवों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए भगवंत मान सरकार ने फसलों में आग लगने की घटनाओं और जानलेवा हादसों को रोकने तथा ऊपर से गुजरने वाली तारों (ओवरहेड लाइनों) के कारण बार-बार होने वाले बिजली कटौती को खत्म करने के लिए बिजली की तारों को जमीनदोज करना शुरू कर दिया है, जिससे गांवों को खतरनाक खंभों और उलझी हुई तारों के जाल से मुक्ति मिलेगी।

इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सतौज में 384 बिजली के खंभे हटा दिए जाएंगे और सड़कों को खोदे बिना जमीनदोज केबलें बिछाई जाएंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस प्रोजेक्ट को आधुनिक बुनियादी ढांचे, निर्विघ्न बिजली सप्लाई और सुरक्षित गांवों पर आधारित रोशन पंजाब की शुरूआत बताया। सतौज मॉडल को पूरे देश के लिए मिसाल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने पंजाब के किसानों से गांवों को तार-मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि जमीनदोज बिजली सप्लाई से गांवों में बिजली के खंभे लगाने को लेकर होने वाली सियासत भी खत्म हो जाएगी।

इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, आज पंजाब के गांवों के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि गांवों को बिजली की तारों के जाल और अनावश्यक खंभों से मुक्त करने का व्यापक प्रोजेक्ट यहीं से शुरू किया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सतौज में बिजली की ऊपर से गुजरने वाली तारों को करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से जमीनदोज किया जाएगा। यह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है और इस पहल से पंजाब पूरे देश के लिए मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में उभरेगा।

प्रोजेक्ट के तकनीकी विवरण के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया, इस प्रोजेक्ट के तहत 7 किलोमीटर हाई टेंशन (एच.टी.) लाइनें, 9.5 किलोमीटर लो टेंशन (एल.टी.) लाइनें और 800 उपभोक्ताओं के घरों को जोड़ने वाली 41 किलोमीटर सर्विस केबल जमीनदोज बिछाई जाएगी। सतौज के 66 के.वी. ग्रिड से गांव से जुड़े तीन 11 के.वी. फीडर और इससे जुड़े 28 ट्रांसफार्मरों की सारी हाई टेंशन लाइनें जमीनदोज हो जाएंगी। इसके बाद 28 ट्रांसफार्मरों से मीटर बॉक्सों तक की सारी लो टेंशन लाइनें भी जमीनदोज की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मीटर बॉक्सों को सारे घरों से जोड़ने वाली केबलों को भी जमीनदोज किया जाएगा, जिससे 384 अनावश्यक बिजली के खंभे हटा दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि जमीनदोज केबलें बिछाने के लिए सड़कें खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जमीनदोज पाइप डालने के लिए ट्रेंचलेस (बिना खुदाई) ड्रिलिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पाइप जमीन से तीन फुट नीचे बिछाए जाएंगे, जो आम लोगों के लिए वरदान साबित होंगे।

बिजली की ऊपरी तारों के खतरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, बिजली के खंभों और ऊपरी तारों से पशुओं और लोगों खासकर बच्चों को करंट लगने का खतरा बना रहता है। ट्रैक्टर, कंबाइन और अन्य वाहनों के ऊपरी तारों से संपर्क में आने पर अक्सर हादसे होते हैं। इसी तरह फसलों में आग लगने की घटनाओं से किसानों को भारी नुकसान होता है। बारिश, तूफान और तेज हवाओं से खंभे और तारें टूट जाती हैं, जिससे बिजली सप्लाई प्रभावित होती है और पावर कॉर्पोरेशन को वित्तीय नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खंभों और तारों का जाल गांवों की सुंदरता को भी प्रभावित करता है। इस प्रोजेक्ट को लोगों के लिए हर पहलू से फायदेमंद बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई टेंशन और लो टेंशन लाइनों के जमीनदोज होने से बिजली की लीकेज खत्म हो जाएगी, जिससे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का घाटा कम होगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पंजाब के इतिहास में मील का पत्थर माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह प्रोजेक्ट मेरी जन्मभूमि से शुरू किया जा रहा है और आज का दिन पंजाब के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस गांव से पंजाब सरकार ने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके बारे में देश के किसी अन्य राज्य ने अभी तक सोचा भी नहीं है। यह प्रोजेक्ट इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आज मेरा सपना साकार हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का सपना बहुत साल पहले देखा गया था।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, पंजाब सरकार ने मावां धीयां सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाएगी। सम्मान राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इसके योग्य होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने बजट में 9,300 करोड़ रुपए रखे हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और तरुणप्रीत सिंह सौंध सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। एक्स पर कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, सपनों के रोशन पंजाब बनाने की ओर एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए आज गांव सतौज में बिजली की तारों को जमीनदोज करने के अत्याधुनिक प्रोजेक्ट की शुरूआत की गई है। यह पहल न केवल गांवों और शहरों की सुंदरता को निखारेगी, बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली कटौती तथा तूफान और तेज हवाओं के दौरान होने वाले हादसों से भी पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। इस प्रोजेक्ट के साथ घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और खेतों को निर्विघ्न और सुरक्षित बिजली सप्लाई मिलेगी, जिससे हर नागरिक के जीवन स्तर में सुधार होगा।

बी.के.आई. समर्थित मॉड्यूल से जुड़े दो व्यक्ति अमृतसर में काबू ; दो हैंड ग्रेनेड बरामद

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/अमृतसर

पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.) समर्थित मॉड्यूल से जुड़े विदेशी हैंडलरों के दो साथियों को दो हैंड ग्रेनेड सहित गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का पदार्फाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां साझा की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अजनाला, अमृतसर के बाजीगर मोहल्ला निवासी अजय तथा फत्तेवाल कलां निवासी जोधबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने हैंड ग्रेनेड बरामद करने के अलावा उनका

काले रंग का हीरो स्प्लेंडर (पीबी 02 ईके 2107) मोटरसाइकिल भी जब्त किया है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बरामद किए गए ग्रेनेड एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य सरकारी संस्थानों एवं बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर पंजाब की शांति और कानून व्यवस्था को भंग करना था।

- बरामद किए गए ग्रेनेड सरकारी संस्थानों को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा थे: डीजीपी गौरव यादव
- आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी

ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि विदेशी हैंडलरों द्वारा अपने साथियों को हैंड ग्रेनेड उपलब्ध करवाए गए हैं और उन्हें आगे अपने किसी अन्य कार्यकर्ता के साथ अमृतसर के लोहारका रोड क्षेत्र में संपर्क स्थापित करने के लिए कहा गया है।

इस पुख्ता सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने नाका लगाकर संदिग्ध अजय और जोधबीर सिंह को रोका और उनकी तलाशी ली। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है ताकि नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा सके।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 36 दिनांक 18-05-2026 को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 तथा बीएनएस की धारा 61(2) के तहत पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एस.एस.ओ.सी.), अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा अप्रैल महीने के दौरान 10 रिश्वतखोरी के मामलों में 12 सरकारी कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अपने अभियान के दौरान अप्रैल महीने में 10 अलग-अलग ट्रैप मामलों में 12 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने सरकारी कर्मचारियों और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं।

उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने पिछले महीने विभिन्न सक्षम अदालतों में 59 विजिलेंस मामलों से संबंधित चालान पेश किए हैं। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों की गहराई से जांच करने के लिए 4 विजिलेंस जांचें भी दर्ज की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि 21 आरोपियों

के खिलाफ 13 आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें 17 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न सक्षम अदालतों ने पिछले महीने ब्यूरो द्वारा दायर और लड़े गए चार रिश्वतखोरी मामलों में फैसला सुनाया, जिसमें 20 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें दो साल से पांच साल तक की कैद तथा 10,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

संक्षिप्त-समाचार

जनगणना फॉर्म में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए प्रतिबंधित शब्दों के इस्तेमाल के मामले में जसवीर गढ़ी द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन से मुलाकात

चंडीगढ़। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए तैयार किए गए फॉर्म में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए प्रतिबंधित शब्दों के इस्तेमाल के मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (नई दिल्ली) के चेयरमैन से मुलाकात की और इन प्रतिबंधित शब्दों के इस्तेमाल को रुकवाने के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जनगणना 2027 की सूचियों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों से अनुसूचित जातियों के लिए इस्तेमाल की गई अपमानजनक और समाज विरोधी शब्दावली को तुरंत हटवाने के लिए राष्ट्रीय आयोग से संपर्क किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास दर्ज एक शिकायत (नंबर 1211/26/पीएसएससीसी/5325-26) का संज्ञान लेते हुए चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी दस्तावेजों में इन शब्दों का लगातार इस्तेमाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) और अनुच्छेद 21 (सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार) का सीधा उल्लंघन करता है। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में मुख्य रूप से सभी आपत्तिजनक शब्दों को जनगणना फॉर्मेट और स्व-गणना पोर्टल से तुरंत हटाने संबंधी मांग की गई है तथा भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपाय भी सुझाए गए हैं।

गांव इटावा आंगनवाड़ी रिनोवेशन कार्य का शुभारंभ

चंडीगढ़ । गांव इटावा की आंगनवाड़ी के रिनोवेशन कार्य का शुभारंभ किया गया। इस रिनोवेशन कार्य के अंतर्गत पेंट-पॉलिश, मार्बल की सफाई, नई टाइल्स, नए दरवाजे एवं अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य करवाए जाएंगे, ताकि आंगनवाड़ी को बच्चों एवं स्थानीय निवासियों के लिए अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधाजनक बनाया जा सके। गांव के छोटे-छोटे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह कार्य शुरू किया गया है, ताकि बच्चे बेहतर वातावरण, नई सोच एवं सकारात्मक माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। लंबे समय से आंगनवाड़ी की मरम्मत की मांग की जा रही थी, जिससे यहां साफ-सफाई बेहतर हो सके तथा बच्चों और स्थानीय निवासियों को बीमारियों एवं अन्य परेशानियों से राहत मिल सके। इस अवसर पर गांव इटावा के सीनियर सिटीजन सरदार सोहन सिंह जी ने नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ करवाया। इस मौके पर मार्केट प्रधान विजय कुमार, सुरेश कुमार, अजीत सवार, राजेंद्र सिंह बिल्ला, बलविंदर कौर, आंगनवाड़ी स्टाफ, उषा आशा वर्कर,जगतार कौर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे तथा सभी ने इस सामाजिक कार्य को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया।

आईवी क्लिनिक्स ने चंडीगढ़ और मोहाली में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट डेंटल, स्किन और हेयर क्लिनिक्स लॉन्च किए

मोहाली। आईवी क्लिनिक्स, एक उभरता हुआ प्रीमियम और अफोर्डेबल फैमिली हेल्थकेयर ब्रांड, ने चंडीगढ़ ट्राइसिटी रीजन में दो स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मल्टी-स्पेशलिटी क्लिनिक्स के लॉन्च की घोषणा की है। ये क्लिनिक्स सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़ और एच एल पी गैलेरिया, सेक्टर 62, मोहाली में स्थित हैं। इन क्लिनिक्स का उद्देश्य एडवांस्ड डेंटल, स्किन और हेयर ट्रीटमेंट्स को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराकर हेल्थकेयर एक्सेस को नए स्तर पर ले जाना है। ह्लस्माइल, स्किन, हेयर – परफेक्टेड ह्ह की फिलॉसफी पर आधारित, आईवी क्लिनिक्स कटिंग-एज मेडिकल टेक्नोलॉजी, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट्स और पेशेंट-फर्स्ट अप्रोच को साथ लाता है, ताकि स्टैंडर्डाइज्ड और हाई-क्वालिटी हेल्थकेयर एक्सपीरियंस दिया जा सके। क्लिनिक्स एडवांस्ड ग्लोबल टेक्नोलॉजीज से लैस हैं, जिनमें आईटेरो डिजिटल डेंटल स्कैनर्स, बायोलेस लेजर डेंटिस्ट्री सिस्टम्स, पपाया ओ पी जी इमेजिंग, अल्मा लेजर्स हेयर रिमूवल इक्विपमेंट और क्योर द्वारा हाइड्राफेशियल सिस्टम्स शामिल हैं।

बजाज जनरल इंश्योरेंस ने पेश किया एमएचसीपी एज+

चंडीगढ़ । 1बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के नाम से प्रचलित) भारत की एक अग्रणी और प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने आज ही ह्यमाय हेल्थ केयर प्लान एज+ (एमएचसीपी एज+) का शुभारंभ किया है। यह एक ह्यकॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंडेमिनिटी प्लान है, यानी कि यह आपकी सेहत के लिए खर्चों की भरपाई करने वाला प्लान है. इसे दिनोंदिन बढ़ते मेडिकल खर्चों के मद्देनजर तैयार किया गया है। इसमें मौजूद सहूलियतों से न केवल आपकी जेब से होने वालों खर्चों में कमी आती है, बल्कि इसे आप अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल भी सकते हैं. एमएचसीपी एज+ को मौजूदा एमएचसीपी की मजबूत बुनियाद पर तैयार किया गया है। इसमें न केवल जरूरी देखभाल के लिए कवरेज मिलता है, बल्कि यह वैकल्पिक राइडर भी पेश करता है. इसलिए ग्राहक अपनी सेहत, उम्र और बजट की बदलती जरूरतों के मुताबिक इसे ढाल सकते हैं. यह पॉलिसी 5 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक के इंश्योरेंस कवरेज का विकल्प पेश करती है।

उच्च रक्तचाप पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

चंडीगढ़ । उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लिवासा द्वारा आज सीपी 67 मॉल में एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान, लोगों को शीघ्र निदान, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, जीवनशैली में बदलाव और समय पर जांच के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया। स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन की थीम पर बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, साथ ही युवाओं को कम उम्र से ही स्वास्थ्य और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए, कार्डियक साइंसेज चेयरमैन डॉ एचके बाली ने कहा, कई लोग जटिलताएं उत्पन्न होने तक उच्च रक्तचाप से अनजान रहते हैं। रक्तचाप की नियमित निगरानी, स्वस्थ जीवनशैली की आदतें और समय पर चिकित्सा परामर्श गंभीर हृदय रोगों के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जागरूकता और रोकथाम हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं। सीईओ अनुराग यादव ने कहा, इस तरह की सामुदायिक जागरूकता पहलों के माध्यम से, हमारा उद्देश्य लोगों को सही ज्ञान से सशक्त बनाना और निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है जो स्वस्थ समुदायों के निर्माण में मदद कर सकती हैं।

खाद सब्सिडी पर अपनी ही वाहवाही करने वाले जाखड़ पर वड़िंग का तंज

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद सब्सिडी के लिए ह्लधन्यवादह्व कहने पर तंज कसते हुए, कहा कि जैसे उन्होंने कोई क्रांतिकारी काम किया हो या यह पहली बार हुआ हो।

वड़िंग ने कहा कि खाद सब्सिडी कई वर्षों से हर सरकार की नीति रही है और प्रधानमंत्री मोदी इसे देने वाले पहले नेता नहीं हैं, जैसा कि जाखड़ लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं।

उन्होंने भाजपा नेता को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने किसानों को खादों के इस्तेमाल को कम करने या उससे परहेज करने की भी सलाह दी थी। उन्होंने सवाल किया कि जब एक तरफ आप खादों पर सब्सिडी देने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ किसानों को इनके इस्तेमाल से बचने के लिए कहते हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की अन्य कृषि लागतें, जैसे डीजल, मजदूरी और बढ़ती महंगाई के मुकाबले कोई भी सब्सिडी पर्याप्त नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ये सभी चीजें उस कथित सब्सिडी के लाभ को खत्म कर देती हैं, जिसे सरकार को हर हाल में किसानों को देना ही पड़ता है। इसके अलावा, सरकार किसानों पर कोई विशेष एहसान नहीं कर रही, क्योंकि किसान ही पूरे देश का पेट भरते हैं।

मान सरकार राज्य के खेल माहौल को बदलने के लिए प्रतिबद्ध : विधायक सुखानंद

सिटी दर्पण संवाददाता
जालंधर

पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से रायजादा हंसराज बैडमिंटन स्टेडियम में 4 दिवसीय पंजाब स्टेट सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 22 मई 2026 तक चलेगी।

टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक एवं पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रधान सरदार अमृतपाल सिंह सुखानंद ने किया। इस मौके पर विधायक सुखानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के खेल माहौल को बदलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को नशों से दूर कर खेलों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार खेल बजट को 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1791 करोड़ रुपये किया गया है, जो खेलों के विकास के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने राज्य में जमीनी स्तर पर बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए एसोसिएशन के प्रयासों की भी सराहना की। पंजाब बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव रितिन खन्ना ने बताया कि टूर्नामेंट को खिलाड़ियों का शानदार समर्थन मिला है। राज्य के 23 जिलों से करीब 400 खिलाड़ियों की 600 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। अंडर-15 और अंडर-17 वर्ग में लड़कों और लड़कियों के कुल 10 इवेंट खेले जा रहे हैं। अगले 4 दिनों में लगभग 500 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबले 22 मई को होंगे और विजेताओं को नकद पुरस्कार व अन्य आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों और कोचों की सुविधा के लिए खाने-पीने और रिफ्रेशमेंट के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं।

इस दौरान एसोसिएशन ने राज्य के दो होनहार बैडमिंटन खिलाड़ियों स्वर्गीय मयंक शर्मा और साहिब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिनकी अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दुखद मृत्यु हो गई थी। उनकी याद में अंडर-15 और अंडर-17 वर्ग में दो विशेष ट्रॉफियां शुरू की गई हैं।

जालंधर की अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मान्या रलहन को फ्रांस में आयोजित सेंट डेनिस ओपन में कांस्य पदक जीतने पर मुख्य अतिथि द्वारा 31,000 रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित भी किया गया।

इस अवसर पर डीबीए के कोषाध्यक्ष पलविंदर जुनेजा, हरप्रीत सिंह, जसवंत सिंह, पंजाब मसीह, धीरज शर्मा, सचिन रत्ती, वरुण कुमार सहित बैडमिंटन जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं।

वित्त मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को पहले चरण के कार्यों के सत्यापित बिल और यू.सी. पोर्टल पर अपलोड करने के दिए निर्देश

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा रंगला पंजाब विकास स्कीम के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्टों की स्थिति का जायजा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को ह्यरंगला पंजाब विकास स्कीमह्ल को तेजी से लागू करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने पहले चरण के कार्यों के सत्यापित बिल और उपयोगिता प्रमाण पत्र तुरंत निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पहले चरण के बाकी बचे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अतिरिक्त मुख्य सचिव जसप्रीत तलवाड़ भी उपस्थित

थे। बैठक का मुख्य केंद्र विकास अभियान के अगले चरण के लिए रणनीतियां तैयार करना रहा। वित्त मंत्री ने स्कीम के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए निर्धारित समय-सीमा की समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि डिप्टी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि दूसरे चरण के सभी कार्य तय समय के भीतर शुरू और पूरे किए जाएं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मई के अंत तक दो विस्तृत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली रिपोर्ट में उन कारणों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए जिनके कारण पहले चरण के कार्य 31 मई तक पूरे नहीं हो सके और दूसरी रिपोर्ट में आने वाले दूसरे चरण के विकास प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए एक व्यापक योजना और समय-सीमा का खाका प्रस्तुत करना होगा। सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर कार्यों की गति बढ़ाने के लिए हर सप्ताह प्रोजेक्टों की समीक्षा करें। इस समीक्षा बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया, जबकि संबंधित प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

अमेरिका के सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर में गोलीबारी, तीन की मौत

दोनों हमलावरों ने खुद को भी उड़ाया

एजेंसी (हि.स.)

वाशिंगटन

संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सैन डिएगो स्थित इस्लामिक सेंटर परिसर में मस्जिद के पास सोमवार को गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई। दावा किया गया है कि इस वारदात को दो नाबालिग बंदूकधारियों ने अंजाम दिया। इसके बाद पास की गली में जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

सूचना पाकर इस्लामिक सेंटर पहुंची पुलिस ने कुछ समय के लिए इलाके में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी। सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्कॉट वाहल ने घटना की पुष्टि की है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्कॉट वाहल ने बताया कि दो संदिग्ध हमलावर पास ही एक गाड़ी के अंदर मृत पाए गए हैं। संदिग्धों की उम्र 17 और 18 साल है।

फोटोः हि.स.

वाहल ने बताया कि घटना की जांच हेट क्राइम (नफरत से जुड़ा अपराध) के तौर पर की जा रही है। सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर के इमाम ताहा हस्सान ने लोगों से नफरत को त्याग कर सद्भावना के साथ रहने की अपील की है। इस परिसर में एक भी मदरसा (स्कूल) भी है। गोलीबारी के समय बच्चे मदरसा में पढ़ रहे थे। गोलियों की तड़तड़ाहट से प्रांगण में अफरातफरी मच गई। सैन डिएगो के पुलिस प्रमुख स्कॉट वाहल ने बताया कि हमले की पहली सूचना सुबह करीब 11:43 बजे मिली। इस घटना से दो घंटे पहले एक महिला ने अपने बेटे के लापता होने की सूचना दी थी। उसने बताया था कि उसके साथ कई हथियार हैं। उसकी गाड़ी भी गायब है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक सेंटर को कोई धमकी नहीं मिली थी। घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। इस्लामिक सेंटर के इमाम ताहा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस घटना से मुस्लिम समुदाय शोक में है। उन्होंने कहा, यह कुछ ऐसा है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी।

इस हमले में इस्लामिक सेंटर का एक गार्ड भी मारा गया है। पुलिस ने उसकी पहचान का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। सैन डिएगो के मेयर टॉड ग्लोरिया ने कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए अब पुलिस तैनात की जाएगी। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा कि वह सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर की घटना से स्तब्ध हैं। कैलिफोर्निया में नफरत की कोई जगह नहीं है।

अमेरिका-ईरान को मनाने में जुटे कतर, सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान, ट्रंप ने हमले को टाला

वाशिंगटन/तेहरान/इस्लामाबाद। दुनिया के प्रमुख और सबसे अहम तेलमार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर खिंची तनाव की तलवारों के बीच कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और पाकिस्तान 'अमेरिका और ईरान' के बीच शांति समझौता कराने के प्रयासों पर लगे हुए हैं। मध्यस्थ की भूमिका में विफलता के बावजूद पाकिस्तान ने हार नहीं मानी है। वह अब भी अपने स्तर पर ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है। कतर, सऊदी अरब और यूएई तीनों मिलकर इस संकट का समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। तीनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वह फिलहाल ईरान पर हमले की अपनी योजना को स्थगित कर दें। अरबी चैनल अल जजीरा, अमेरिकी चैनल सीबीएस न्यूज और पाकिस्तान के चैनल दुनिया न्यूज की रिपोर्ट में ईरान-अमेरिका के मध्य छिड़े विवाद की सुर्खियों को विस्तार से तरजीह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले नियोजित हमले को टाल दिया है। उन्होंने कहा, इस समय शांति समझौते को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जल्द ही शांति समझौता कराने के लिए किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपनी मुख्य शर्त पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को हर हाल में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। साथ ही कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर पश्चिम एशिया के सहयोगी देश संतुष्ट हो जाते हैं तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि इसलिए अमेरिका अब मंगलवार को ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के अनुसार, यह समझौता अमेरिका और मध्य-पूर्व के देशों को स्वीकार्य होगा। राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा से पहले ईरान ने कहा था कि उसने संभावित शांति समझौते के लिए शर्तों का एक और संशोधित मसौदा भेजा है। बताया जा रहा है कि यह मसौदा पाकिस्तान के जरिये के भेजा गया है।

नेपाल ने श्रम समझौता करने के लिए 16 देशों को भेजा प्रस्ताव, एक ने भी नहीं दिया जवाब

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

फोटोः हि.स.

नेपाल सरकार ने विदेशी रोजगार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से 16 देशों के साथ श्रम समझौता प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने उन देशों को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन अब तक किसी देश ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे ने कहा कि 16 देशों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से श्रम समझौते का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि, अब तक किसी भी देश ने नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। सरकार ने एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों के साथ श्रम समझौता करने के उद्देश्य से प्रस्ताव भेजा है।

घिमिरे के मुताबिक मंत्रालय ने वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, माल्टा, मालदीव, सर्बिया, साइप्रस, लक्जमबर्ग, ब्रुनेई, पोलैंड, बोस्निया एंड हजेगोविना, क्रोएशिया और बेल्जियम को श्रम समझौते का प्रस्ताव भेजे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इनमें से किसी भी देश ने अब तक नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। वर्तमान में नेपाल का केवल 13 देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता है, जबकि दुनिया के 170 से अधिक देशों में नेपाली श्रमिक कार्यरत हैं। बड़ी संख्या में नेपाली युवा ऐसे देशों में वैदेशिक रोजगार के लिए जाते हैं, जहां नेपाल का श्रम समझौता नहीं है। इससे आर्थिक ठगी और श्रम शोषण का खतरा बढ़ रहा है। इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार नए देशों के साथ श्रम समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा, विदेश रोजगार के लिए विभिन्न देशों में जाने वाले लगभग 48 प्रतिशत नेपाली नागरिक व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लेते हैं। नेपाल के कानून में यह प्रावधान है कि नेपाल सरकार, कूटनीतिक संबंध स्थापित देशों की सरकारों के साथ संधि या समझौता कर, सरकारी निकायों या नेपाल सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से कामदार भेज सकता है। इन्हीं कानूनी प्रावधानों के आधार पर सरकार नेपाली कामदार जाने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता और समझदारी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता घिमिरे ने कहा, 'हम श्रम समझौते के लिए प्रस्ताव भेजने के बाद से संबंधित देशों के साथ लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। उनकी ओर से प्रतिक्रिया आने का इंतजार है। जवाब क्यों नहीं आया, इस बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।' श्रम समझौता करने की इच्छा से प्रस्ताव भेजे गए हैं। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुंग का कहना है कि श्रम समझौता श्रमिकों की कानूनी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण आधार है।

नेपाल में प्रवेश कर रहे भारतीय से 570 ग्राम सोना और 20 हजार अमेरिकी डॉलर मिले, गिरफ्तार

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

काठमांडू

नेपाल के पूर्वी झापा के मेचीनगर स्थित कांकडभिट्टा सीमा क्षेत्र में सशस्त्र प्रहरी बल और कस्टम कार्यालय की संयुक्त टीम ने 570 ग्राम सोना तथा 20 हजार अमेरिकी डॉलर व अन्य विदेशी मुद्रा के साथ एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के अनुसार, भारत से सिटी सफारी वाहन के जरिए नेपाल आ रहे भारत निवासी 39 वर्षीय परम पाठक को विशेष सूचना के आधार पर मंगलवार सुबह जांच के दौरान पकड़ा गया। उसके पास 570 ग्राम सोना, 20 हजार अमेरिकी डॉलर तथा 85 हजार 410 भारतीय रुपये मिले हैं। साथ ही एक भारतीय आधार कार्ड, दो मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क, एक बैंक चेक तथा सात सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सशस्त्र प्रहरी के प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक बिष्णु प्रसाद भट्ट ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए पाठक को बरामद सामग्री के साथ मेची भंसार कार्यालय कांकडभिट्टा को सौंप दिया गया है। वह किस उद्देश्य से नेपाल में प्रवेश कर रहा था, इसकी फिलहाल जांच जारी है।

ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ बिहार में आज 40 हजार दवा दुकानें रहेगी बंद

पटना। बिहार सहित पूरे देशभर में ऑनलाइन कंपनियों की ओर से दवा की घर-घर सप्लाई के खिलाफ देशभर की दवा दुकान 20 मई को 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। इस संबंध में बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने बताया कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के कॉल पर बिहार ने पूरा समर्थन दिया है। 19 मई की रात 12:00 बजे से 20 मई 2026 की रात 12:00 तक 24 घंटे के लिए राज्य के सभी 40000 से अधिक दवा दुकानें बंद रहेंगी। प्रसन्न कुमार सिंह, अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने फोन पर बताया कि केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर हम लोग 20 मई को देशभर की दवा दुकानों को बंद रखने का कॉल दिए हैं। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को सही समय पर उचित मूल्य पर सही दवाओं की आपूर्ति हो, यह वह लोग चाहते हैं। लेकिन दवाओं के इस महत्वपूर्ण व्यापार में ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली, डुप्लीकेट और अवैध दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से कर रही हैं। इससे समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि जो दवा दुकानदार हैं उनके लिए दवा की आपूर्ति करने से संबंधित विभिन्न विभागीय निर्देशों को पालन करना पड़ता है।

ऋषिकेश में उज्जैन एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतरे

एजेंसी (हि.स.)

ऋषिकेश

फोटोः हि.स.

उत्तराखंड के ऋषिकेश में योग नगरी रेलवे स्टेशन के पास सोमवार देररात उज्जैन एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा खान गांव क्षेत्र में रात करीब 10 बजे हुआ। राहत की बात यह रही कि ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

बताया गया है कि रेलवे यार्ड में मेंटेनेंस के दौरान ट्रेन की संटिंग की जा रही थी। इसी दौरान तकनीकी खराबी अथवा ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला और लोगों को ट्रैक से हटाया। आनन-फानन में रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। देर रात तक रेस्क्यू उपकरणों का इंतजार किया जाता रहा। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार मंगलवार सुबह ट्रेन 6:15 में रवाना होती है। अभी रवाना नहीं हुई है। रेस्टोलेशन का कार्य जारी है। मौके पर संबंधित अधिकारी मौजूद हैं।

आरपीएफ निरीक्षक सरोज कुमार ने बताया कि उज्जैनी गाड़ी की संटिंग के दौरान एक डिब्बा पटरी से उतर गया था। सूचना मिलते ही सुरक्षा टीम मौके पर पहुंच गई थी। हालांकि घटना को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ट्रेन की मूवमेंट, सुरक्षा मानकों और लोको पायलट की मौजूदगी को लेकर शंकाएं जताई हैं। लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद अधिकारी स्पष्ट जानकारी देने से बचते नजर आए, जिससे संदेह और बढ़ गया। वहीं कुछ लोगों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डिब्बों के पटरी से उतरने के दौरान लोहे के टकराने की तेज आवाज दूर तक सुनाई दी। रात के सन्नाटे में हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। फिलहाल रेलवे विभाग मामले की जांच में जुटा है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

संक्षिप्त-समाचार

मणिपुर में भारत-म्यांमार सीमावर्ती इलाकों से कई उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल। मणिपुर में सुरक्षा बलों और केंद्रीय एजेंसियों ने उग्रवाद विरोधी अभियान तेज करते हुए प्रतिबंधित संगठनों पीएलए, यूएनएलएफ और केवाईकेएल से जुड़े कई सक्रिय उग्रवादियों को भारत-म्यांमार सीमावर्ती इलाकों के अलग-अलग जिलों से बीते 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। मणिपुर पुलिस ने मंगलवार को दी गई आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय बलों ने तेंगनौपाल जिले के मोरेह थाना क्षेत्र में बीपी(बॉर्डर पिलर)-77 और बीपी-79 के बीच अभियान चलाकर पीएलए के तीन सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान थोउबल जिले के चरंगपत निवासी वांगथोई नाहाकपम उर्फ लिंगजेल (20), इंफाल पूर्व जिले के कोंगबा निवासी नानाओबा नांदेइबाम उर्फ अंगौ (19) तथा बिष्णुपुर जिले के नाम्बोल निवासी मालेम ओइनाम उर्फ मणिथोइबा (20) के रूप में हुई है। वहीं, सुरक्षा बलों ने आरपीएफ/पीएलए के एक सक्रिय सदस्य चिंगलेन अथोकपम उर्फ इबुंगो (30) को भी गिरफ्तार किया। वह इंफाल पूर्व जिले के लामलाई थाना क्षेत्र स्थित पुंगडोंगबाम मयाई लेकाई का निवासी है। वहीं, एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों ने थोउबल जिले के यैरिपोक थाना क्षेत्र अंतर्गत यैरिपोक बाजार इलाके में अभियान चलाकर यूएनएलएफ (कोइरेंग) के सक्रिय उग्रवादी थांगजाम धर्मेंद्र सिंह उर्फ वायेनबा उर्फ वॉल्यूम (26) को गिरफ्तार किया। वह अवैध हथियार और गोला-बारूद की तस्करी में संलिप्त बताया गया है। उसके कब्जे से एक 9 एमएम मैगजीन, एक मोबाइल फोन के साथ दो सिम कार्ड, एक पावर बैंक एवं यूएसबी केबल तथा एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया। इसके अलावा इंफाल पश्चिम जिले के लामफेल थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से केवाईकेएल के दो सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों में इराम सिफाई मामांग लेकाई निवासी सोरोक्हाइबाम प्रियचंद सिंह उर्फ सजाओ (39) तथा उरीपोक ताखेल्लामबाम लेकाई निवासी मोइरंगथेम नाओबी सिंह (47) शामिल हैं। प्रियचंद सिंह को रिम्स के निकट से जबकि नाओबी सिंह को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने इनके पास से दो मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड भी बरामद किया है।

कोलकाता एसटीएफ की कार्रवाई, बिहार के पूर्णिया में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़

कोलकाता। कोलकाता पुलिस की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने बिहार पुलिस के सहयोग से पूर्णिया जिले में चल रही एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मंगलवार दोपहर एसटीएफ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि यह कार्रवाई 18 मई की शाम गुप्त सूचना के आधार पर की गई। एसटीएफ कोलकाता पुलिस, एसटीएफ बिहार और दमदाहा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पूर्णिया जिले के हरिपुर गांव स्थित मिथु कुमार और गब्बर राय के घर पर छापा मारा। जांच में पता चला कि वहां भूतल पर कागज की प्लेट बनाने की फैक्ट्री की आड़ में भूमिगत गुप्त कक्ष बनाकर अवैध हथियार निर्माण का काम चलाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस भूमिगत कक्ष को विशेष रूप से इस तरह तैयार किया गया था ताकि हथियार निर्माण के दौरान होने वाली आवाज को बाहर आने से रोका जा सके। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से चार आरोपितों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान मिथु कुमार, गब्बर राय, मोहम्मद अनवर खान और मोहम्मद आफताब आलम उर्फ लादन के रूप में हुई है। बाद में इस पूरे गिरोह के मुख्य सरगना सूरज कुमार को भी बिहार के मुंगेर जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फैक्ट्री से पांच अर्धनिर्मित पिस्तौल, पांच पिस्तौल बॉडी, चार पिस्तौल बट, एक लेथ मशीन, एक मिलिंग मशीन, एक ड्रिलिंग मशीन और एक ग्राइंडिंग एवं पॉलिशिंग मशीन बरामद की। इसके अलावा भारी मात्रा में कच्चा माल और अवैध हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं। एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दमदाहा थाने में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चेन्नई में पांच ठिकानों पर ईडी का छापा

चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह से नगर में पांच से अधिक स्थानों पर छापा मारा है। जानकारी के अनुसार ईडी की यह कार्रवाई नगर के अयनवारम और थिरुमंगलम क्षेत्रों में पुरानी कारों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक फाइनेंसर के घर पर चल रही है। जानकारी के अनुसार, बैंकों से ऋण लेकर धोखाधड़ी करने और अवैध धन लेन-देन से जुड़ी शिकायतों के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने लागू किए सख्त खर्च नियंत्रण और प्रशासनिक सुधार उपाय

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और सरकारी खर्च में कटौती के उद्देश्य से कई सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी एक अत्यावश्यक निर्देश में सभी सरकारी विभागों और जिला प्रशासन को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। यह पहल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा हाल ही में ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग और प्रशासनिक कार्यों में डिजिटल प्रणाली के विस्तार पर दिए गए जोर के अनुरूप मानी जा रही है। जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों को अनावश्यक ईंधन खपत कम करने, डिजिटल प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रत्येक विभाग को तात्कालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरचित 'कार्ययोजना' तैयार करनी होगी। मुख्य सचिव ने प्रशासनिक व्यवस्था में लागू किए जाने वाले सात प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इनमें वर्चुअल बैठकों के उपयोग को बढ़ाना प्रमुख है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां संभव हो, वहां भौतिक बैठकों की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल मंचों का उपयोग किया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित किए बिना उपयुक्त मामलों में घर से काम करने की व्यवस्था की संभावना पर विचार किया जाए। सरकार ने ईंधन बचत के तहत अनावश्यक सरकारी यात्राओं में कमी लाने पर भी जोर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, कार पूलिंग अपनाने और सरकारी कार्यों में धीरे-धीरे विद्युत वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

सॉल्वेंट प्लांट में बॉयलर फटा, मशीन ऑपरेटर जिंदा जला, धमाके के बाद मची भगदड़

एजेंसी (हि.स.)

सतना

मध्य प्रदेश के सतना जिले में सोमवार देर रात एक भीषण हादसा हो गया। यहां अमरपाटन रोड स्थित विद्याश्री सॉल्वेंट प्लांट में अचानक बॉयलर फटने से पूरे परिसर में आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की बस्तियां दहल उठीं और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में मशीन ऑपरेटर दिलावर सिंह उर्फ पिंकू तिघरा (45) की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मन्नू केवट समेत कई मजदूर झुलस गए।

घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्लांट में रोज की तरह काम चल रहा था। इसी दौरान देर रात अचानक तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया। देखते ही देखते आग ने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही कर्मचारियों में भगदड़ मच गई।

फोटोः हि.स.

मशीन ऑपरेटर दिलावर सिंह आग की भीषण लपटों में फंस गए और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। भीषण आगजनी की चपेट में प्लांट में काम करने वाले मन्नू केवट समेत कुल पांच मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि अन्य घायलों की पहचान देर रात तक नहीं हो सकी थी। आग लगने के बाद कुछ समय तक एक कर्मचारी के लापता होने की भी सूचना रही। बताया जा रहा है कि प्लांट में धान की भूसी से राइस ब्रान ऑयल तैयार किया जाता था। परिसर में भारी मात्रा में भूसी और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। आग की ऊंची लपटें पास की बस्ती तक पहुंचने लगीं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। भूसी के बड़े स्टॉक में लगी आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीम राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह सॉल्वेंट प्लांट शहर के सराफा कारोबारी सौरभ जैन की राइस मिल परिसर में संचालित हो रहा था। प्लांट को बिहार के एक व्यापारी ने करीब 8 लाख रुपए प्रतिमाह किराए पर लिया हुआ था। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला।

1475 पीस प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ दो युवक गिरफ्तार, बुलेट बाइक जब्त

सुपौल। शहर में पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके पास से 2 एमएल के कुल 1475 पीस इंजेक्शन और एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक संदिग्ध सामान के साथ इलाके से गुजर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान रणवीर कुमार और रजनीश कुमार के रूप में हुई है। रणवीर कुमार खरेल पुरनवास वार्ड-16 के निवासी बताए गए हैं, जबकि रजनीश कुमार नयानगर सितुहर वार्ड-05 के रहने वाले हैं। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में 2 एमएल इंजेक्शन बरामद किया। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बुलेट मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। बरामद इंजेक्शन किस प्रयोजन के लिए लाए जा रहे थे, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

रिनिकी भुइयां शर्मा मामले में रणदीप सुरजेवाला को पुलिस का समन

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

गुवाहाटी

असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को समन जारी कर 23 मई को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मामले के संबंध में की गई है।

सूत्रों के अनुसार, रिनिकी भुइयां शर्मा के खिलाफ कथित रूप से मनगढ़ंत और भ्रामक जानकारी फैलाए जाने के आरोपों की जांच के दौरान यह समन जारी किया गया।

यह कार्रवाई कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से क्राइम ब्रांच द्वारा की गई लंबी पूछताछ के बाद सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान खेड़ा ने स्वीकार किया कि संबंधित जानकारी कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। क्राइम ब्रांच अब कथित फर्जी सूचनाओं के प्रसार और उससे जुड़े संचार तंत्र की जांच कर रही है।

हरे निशान पर खुला शेयर बाजार सेंसेक्स 295 अंक उछला

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बाजार के दोनों प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स में 295 अंक और निफ्टी में 83 अंकों की तेजी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स शुरूआती कारोबार में 294.79 अंक यानी 0.39 फीसदी की उछाल के साथ 75,609.83 पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेज (एनएसई) का निफ्टी भी 82.60 अंक यानी 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ 23,760 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

सेंसेक्स की 30 में से 20 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ खुले हैं और बाकी 9 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ लाल निशान में खुले। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों ने बिना किसी बदलाव के कारोबार कर रहा है। वहीं, एनएसई निफ्टी की 50 में से 33

फोटोः हि.स.

कंपनियों के शेयरों में तेजी दिख रहा है। वहीं, बाकी की सभी 17 कंपनी के शेयरों ने गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मंगलवार के कारोबार में निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा खरीदारी है, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली है। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपये की विनमय दर शुरूआती कारोबार में 18 पैसे टूटकर 96.38 प्रति डॉलर पर ट्रेंड कर रही है। उल्लेखनीय है कि इससे एक दिन पहले सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी मामूल बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 77.05 अंकों की वृद्धि के साथ 75,315.04 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 6.45 अंकों की बढ़त के साथ 23,649.95 के स्तर पर बंद हुआ था।

आरजी कर मामला

संदीप घोष के खिलाफ अभियोजन की अनुमति

सत्य को दबाया नहीं जा सकता: मुख्यमंत्री शुभेंदु

एजेंसी (हि.स.)

कोलकाता

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक-छात्रा के कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में राज्य सरकार ने अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार रात एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए इसे 'न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम' बताया।

मुख्यमंत्री ने पोस्ट पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश की प्रति भी साझा की। चूंकि संदीप घोष सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक थी। मुख्यमंत्री अधिकारी ने लिखा कि आरजी कर अस्पताल में नौ अगस्त

फोटोः हि.स.

2024 को हुई चिकित्सक-छात्रा की 'निर्मम हत्या और दुष्कर्म' की घटना में तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी को कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक रोके रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि 'कानून से ऊपर कोई नहीं है और सत्य को हमेशा दबाकर नहीं रखा जा सकता।' आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल एवं सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष की आपराधिक गतिविधियां और कर्तव्य में लापरवाही भारतीय न्याय संहिता की धारा 120बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा सात के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती हैं। इसके साथ ही धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत भी मामला दर्ज किए जाने योग्य पाया गया है। इसी आधार पर संदीप घोष के साथ-साथ 'मा तारा ट्रेडर्स', 'ईशान कैफे' और 'खामा लोहा' के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू की गई है।

सरकारी आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। उधर, पीड़िता की मां, जो हाल ही में पानीहाटी से भाजपा विधायक निर्वाचित हुई हैं, ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल अन्य लोगों को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की है। पीड़िता के माता-पिता लगातार दावा करते रहे हैं कि इस घटना में केवल दोषी करार दिया गया संजय राय ही शामिल नहीं था, बल्कि कई अन्य लोग भी इसमें संलिप्त थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी।

विकेट आसान नहीं था, इसलिए अंत तक टिके रहना जरूरी था: ईशान किशन

कहा, कीपिंग के वक्त ही समझ गया था, आसान नहीं होगी चेन्नई की डगर

एजेंसी (हि.स.)
चेन्नई

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बल्लेबाज ईशान किशन ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ सोमवार रात शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। चेन्नई की धीमी और चुनौतीपूर्ण पिच पर 47 गेंदों में 70 रन बनाने वाले ईशान ने मैच के बाद कहा कि विकेट आसान नहीं था और ऐसे में उनकी कोशिश अंत तक बल्लेबाजी करने की थी।

ईशान किशन ने बताया कि विकेटकीपिंग करते समय ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि 180 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा।

मैच के बाद उन्होंने कहा, जब मैं विकेटकीपिंग कर रहा था, तभी मुझे लगा कि यह विकेट बिल्कुल आसान

फोटोः हि.स.

नहीं है। खासकर जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे और स्लोअर गेंदें प्रभावी हो रही थीं। मुझे महसूस हुआ कि इस लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल रहेगा। ऐसे में नंबर-3 बल्लेबाज होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अंत तक खेलूं और मैच खत्म करके आऊं। ईशान तीसरे ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे और लगभग अंत तक क्रीज पर डटे रहे। जब हैदराबाद को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए थे, तब वह आउट हुए। उनकी इस पारी ने टीम की जीत की नींव रखी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ खुद पर भरोसा बनाए रखने की बात थी। कई बार परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन आपको खुद पर शक नहीं करना चाहिए। मैं बस चीजों को सरल रखना चाहता था और जितने ज्यादा ओवर संभव हो सके बल्लेबाजी करना चाहता था। ईशान ने आगे कहा कि बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण गेंदबाजों के लिए लगातार सही एरिया में गेंदबाजी करना आसान नहीं होता। ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की साझेदारी ने मैच का रुख बदल दिया। दोनों बल्लेबाज तब साथ आए जब हैदराबाद का स्कोर 56/2 था और रनगति 10 रन प्रति ओवर से ऊपर पहुंच चुकी थी। हेनरिक क्लासेन ने भी मैच के बाद पिच को चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, शुरूआत में मैंने कुछ गेंदें रोकीं, लेकिन फिर खुद से कहा कि मैं इस तरह बल्लेबाजी नहीं कर सकता।

ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे कप्तान साबित होंगे, लेकिन बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत : स्टीफन फ्लेमिंग

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का समर्थन करते हुए कहा है कि वह भविष्य में फ्रेंचाइजी के लिए बेहतरीन कप्तान साबित होंगे, हालांकि इस सीजन में उनकी बल्लेबाजी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स को सोमवार को पांच विकेट से मिली हार के बाद फ्लेमिंग ने कहा कि ऋतुराज को बल्लेबाजी में और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। फ्लेमिंग ने मैच के बाद कहा, मुझे लगता है कि ऋतुराज और बेहतर कर सकते हैं। वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वह शीर्ष क्रम के शानदार बल्लेबाज रहे हैं। लेकिन इस सीजन में उन्होंने अपने करियर के मुताबिक न तो उतने रन बनाए हैं और न ही उसी गति से रन बनाए हैं। यह ऐसी चीज है जिस पर वह जरूर काम करेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद ने सोमवार को चेन्नई में खेले गए मुकाबले में सीएसके को एक ओवर शेष रहते पांच विकेट से हरा दिया। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अब लगातार तीसरे सीजन प्लेऑफ में पहुंचने से चूकती नजर आ रही है। ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी, खासकर पावरप्ले में धीमी शुरुआत, इस सीजन लगातार चर्चा का विषय रही है। हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी वह शुरुआती छह ओवर में 11 गेंदों पर सिर्फ 9 रन ही बना सके। फ्लेमिंग ने पिछले सीजन की चोट का जिक्र करते हुए कहा,कम से कम इस साल वह पूरे समय टीम के साथ थे।

मलेशिया मास्टर्स 2026: लक्ष्य सेन पर रहेंगी भारत की निगाहें

सिंधु और सात्विक-चिराग टूर्नामेंट से बाहर

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

कुआलालंपुर में आज (मंगलवार) से शुरू हो रहे मलेशिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती की अगुवाई लक्ष्य सेन करेंगे। हालांकि इस बार भारतीय दल में कई बड़े नाम शामिल नहीं हैं। भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी. वी. सिंधु, किदांबी श्रीकांत, युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा ने इस बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 500 प्रतियोगिता से दूरी बनाई है।

विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान पर मौजूद लक्ष्य सेन के लिए कुआलालंपुर अब तक खास सफल नहीं रहा है। वह मलेशिया मास्टर्स और मलेशिया ओपन में कभी दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ सके हैं। पहले दौर में उनका मुकाबला इंडोनेशिया के युवा खिलाड़ी मोहम्मद जाकी उबैदिलाह से होगा, जिन्होंने पिछले जूनियर विश्व चैंपियनशिप में

फोटोः हि.स.

रजत पदक जीता था। यदि लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं तो उनका सामना दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी क्रिस्टो पोपोव से हो सकता है। पुरुष एकल वर्ग में भारत की ओर से एच. एस. प्रणय, किरण जॉर्ज और थारुन मन्नेपल्ली भी चुनौती पेश करेंगे। प्रणय ने 2023 में इसी टूर्नामेंट का खिताब जीता था, लेकिन इस बार पहले दौर में उनका मुकाबला जापान के छठी वरीयता प्राप्त कोडाई नाराओका से होगा। महिला एकल में भारत की ओर से देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, मालविका बंसोड़, ईशारानी बरुआ और तान्या हेमंत हिस्सा लेंगी।

17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर विशेष नजरें रहेंगी। वह पहले दौर में थाईलैंड की पिचामोन ओपाटनिपुथ से भिड़ेंगी। तन्वी ने पिछले वर्ष यूएस ओपन में इसी खिलाड़ी को हराया था। वहीं, अनमोल खरब भी चर्चा में हैं। पिछले सप्ताह बैंकॉक में उन्होंने चीन की विश्व नंबर चार चेन यू फी के खिलाफ निर्णायक गेम में 11-2 की बढ़त गंवा दी थी। इस बार पहले दौर में उनका सामना डेनमार्क की आठवीं वरीयता प्राप्त लाइन कजाएर्सफेल्ट से होगा। पुरुष युगल में भारत की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी हरिहरन अम्साकरुनन और एम. आर. अर्जुन ही ड्रॉ में शामिल हैं। पहले दौर में उनका मुकाबला फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी से होगा। महिला युगल में अश्विनी भट्ट-शिखा गौतम तथा रुतुपर्णा पांडा-श्वेतपर्णा पांडा की जोड़ियां उतरेंगी।

मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर-रुत्विका गड्डे और आशित सूर्य-अमृता प्रमुथेश की जोड़ियां भारत की चुनौती पेश करेंगी।

भारतीय शटलरों के लिए आगामी तीन महीने बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अगस्त में होने वाली विश्व चैंपियनशिप और सितंबर-अक्टूबर में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी करनी है।

स्पेन को बड़ा झटका: लामिन यामाल विश्व कप के पहले मैच से बाहर

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

स्पेन फुटबॉल टीम को फीफा विश्व कप 2026 शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है। स्टार युवा फॉरवर्ड लामिन यामाल हैमस्ट्रिंग चोट के कारण 15 जून को केप वर्डे के खिलाफ होने वाले शुरूआती मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। यह जानकारी 'द एथलेटिक' की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, यामाल अभी पूरी तरह फिट नहीं हो सके हैं और उनके 21 जून को सऊदी अरब के खिलाफ होने वाले दूसरे ग्रुप मुकाबले में खेलने पर भी संशय बना हुआ है।

18 वर्षीय यामाल को यह चोट 22 अप्रैल को एफसी बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए सेल्टा वीगो के खिलाफ मैच में लगी थी। उस मुकाबले में पेनल्टी पर गोल करने के दौरान उनकी बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट आ गई थी, जिसके बाद वह क्लब सीजन के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए थे। दूसरी

फोटोः हि.स.

ओर, बार्सिलोना के ही मिडफील्डर फरमिन लोपेज भी चोटिल होकर लगभग पूरे विश्व कप से बाहर हो गए हैं। रियल बेटिस के खिलाफ मैच के पहले हाफ में उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी। स्पेन अपना पहला मुकाबला 15 जून को अमेरिका के अटलांटा में केप वर्डे के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद टीम 21 जून को सऊदी अरब और 26 जून को उरुग्वे से भिड़ेगी। उरुग्वे के खिलाफ यह मुकाबला मेक्सिको के ग्वाडलाहारा में खेला जाएगा।

फीफा की ताजा पुरुष विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद स्पेन अपनी 26 सदस्यीय विश्व कप टीम की घोषणा अगले सोमवार को करेगा।

आरोन हार्डी बने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नए शेफील्ड शील्ड कप्तान

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

सैम व्हाइटमैन की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी, 2026-27 सीजन से करेंगे टीम की अगुवाई

ऑलराउंडर आरोन हार्डी को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। वह आगामी 2026-27 सीजन से सैम व्हाइटमैन की जगह टीम की कमान संभालेंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रेड-बॉल टीम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। तीन बार शेफील्ड शील्ड खिताब जिताने वाले मुख्य कोच एडम वोग्स के पद छोड़ने के बाद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर ब्यू कैसन को शेफील्ड शील्ड और वनडे कप टीमों का नया मुख्य कोच बनाया गया है। कैसन इससे पहले लंबे समय तक टीम के बल्लेबाजी कोच रहे थे।

सैम व्हाइटमैन ने एडम वोग्स के कार्यकाल में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए 38 शेफील्ड शील्ड मैचों में कप्तानी की। उनकी कप्तानी में टीम ने 2022-23 और 2023-24 में लगातार दो बार खिताब जीता था। वह जॉन इनवैरिटी, ग्रेम वुड और टॉम मूडी के बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को एक से अधिक शील्ड जिताने वाले चौथे कप्तान बने थे। हालांकि, व्हाइटमैन ने इंग्लैंड की काउंटी टीम यॉर्कशायर के साथ लंबी अवधि का अनुबंध किया है और दोहरी नागरिकता के कारण वह अब विदेशी खिलाड़ी के रूप में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे। इसी कारण टीम प्रबंधन ने नई नेतृत्व व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया। 27 वर्षीय आरोन हार्डी को लंबे समय से भविष्य का कप्तान माना जा रहा था। उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया-ए टीम की कप्तानी की थी, जबकि 2025 में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी टीम का नेतृत्व संभाला था। इसके अलावा, 2023-24 बिग बैश लीग में एश्टन टर्नर की गैरमौजूदगी में उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स की कप्तानी भी की थी। कप्तान बनाए जाने पर हार्डी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी एक बयान में कहा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड टीम की कप्तानी मिलना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। यह टीम मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे पास शानदार संस्कृति और बेहतरीन खिलाड़ियों का समूह है। मैं उत्साहित हूं। उन्होंने आगे कहा, मैंने पिछले कुछ वर्षों में टीम के नेताओं और खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं अपनी शैली में नेतृत्व करते हुए ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं, जहां पूरी टीम बेहतर प्रदर्शन कर सके। मुख्य कोच ब्यू कैसन ने भी हार्डी की कप्तानी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, आरोन हार्डी टीम के भीतर बेहद सम्मानित खिलाड़ी हैं। उनकी तैयारी, दबाव में शांत रहने की क्षमता और साथियों के प्रति उनका व्यवहार उन्हें बेहतरीन कप्तान बनाता है। कैसन ने सैम व्हाइटमैन की कप्तानी की भी सराहना करते हुए कहा कि उनकी भूमिका टीम के लिए आगे भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

गौरतलब है कि हार्डी ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट-बॉल टीमों के करीब हैं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण कुछ शेफील्ड शील्ड मुकाबले मिस कर सकते हैं। उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद जून में बांग्लादेश दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में भी शामिल किया गया है।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए ब्राजील टीम का ऐलान, नेमार की वापसी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

ब्राजील पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कार्लो एंचेलोटी ने सोमवार को फीफा विश्व कप 2026 के लिए टीम का ऐलान कर दिया। टीम में स्टार फुटबॉलर नेमार की वापसी हुई है, जो 2023 के बाद पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल हुए हैं। 34 वर्षीय नेमार अपने करियर का चौथा फीफा विश्व कप खेलेंगे। वह ब्राजील के लिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 128 मैचों में 79 गोल किए हैं।

रियो डी जेनेरियो के म्यूज़ियम ऑफ टुमॉरो में जब एंचेलोटी ने नेमार का नाम घोषित किया तो वहां मौजूद समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ब्राजील को फीफा विश्व कप 2026 में मोरक्को, हैती और स्कॉटलैंड के साथ ग्रुप में रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरूआत 13 जून को मोरक्को के खिलाफ करेगी।

फीफा विश्व कप 2026 के लिए ब्राजील टीम

गोलकीपरः एलिसन, एडर्सन, वेवर्टन

डिफेंडरः मार्किन्होस, गेब्रियल मागाल्हाएस, ब्रेमर, लियो परेरा, डेनिलो, वेस्ले, डगलस सैंटोस, एलेक्स सैंड्रो, इबानेज

मिडफील्डरः ब्रूनो गुइमारेस, कासेमिरो, डेनिलो एस., लुकास पाक्वेटा, फाबिन्हो

फॉरवर्डः विनीसियस जूनियर, राफिन्हा, गेब्रियल मार्टिनेली, एंड्रिक, इगोर थियागो, मथियस कुन्हा, नेमार, लुइज हेनरिक, रायन।

निजी जिंदगी की हलचल के बीच कान्स पहुंचीं मौनी रॉय

अभिनेत्री मौनी रॉय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने व्यवसायी पति सूरज नांबियार से अलग होने की घोषणा की थी। इसी बीच अब मौनी ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में अपनी शानदार मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींच लिया है। कान्स से सामने आई उनकी ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिन पर फैंस लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

मौनी अपनी आगामी फिल्म 'बॉम्बे स्टोरीज' के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मार्शे डू फिल्म में शामिल हुईं। अभिनेत्री ने कान्स से तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, कान्स और के ओस ! बोनजोर। तस्वीरों में मौनी ब्लैक कॉलर वाली मिनी ड्रेस, स्टॉकिंग्स और ओवरसाइज्ड कोट में बेहद स्टाइलिश नजर आ रही हैं। उनका यह फैशन लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। कान्स रवाना होने से पहले उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखा गया था, जहां वह पैपराजी से बचते हुए सीधे फ्रांस के लिए निकल गई थीं।

वर्कफ्रंट से ज्यादा इस समय मौनी की निजी जिंदगी चर्चा में है। मौनी और सूरज नांबियार ने 2022 में गोवा में शादी की थी, लेकिन अब दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों ने अपने अलगाव की जानकारी दी थी। हालांकि अभिनेत्री ने साफ किया कि वह सूरज के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाए रखेंगी। फिलहाल दोनों के अलग होने की वजह सामने नहीं आई है।

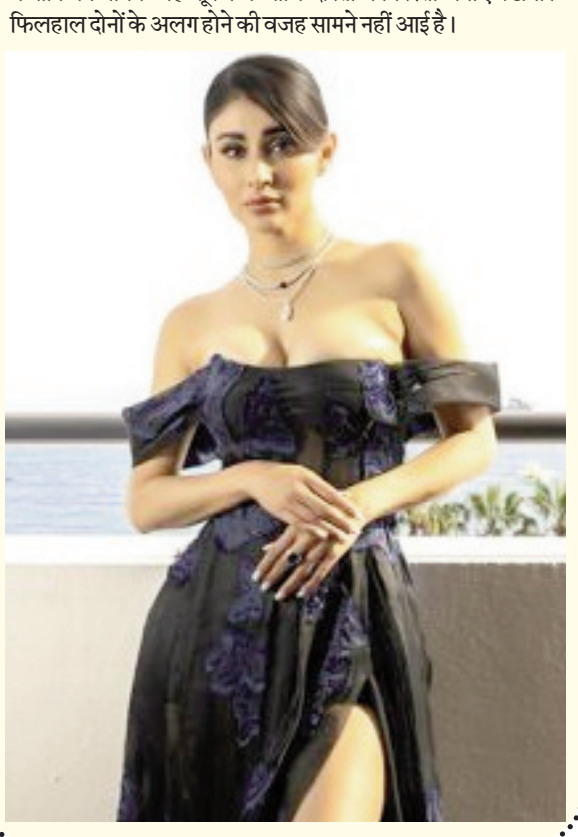

सूर्या की 'करप्पू' के सामने टिक नहीं पाई 'पति पत्नी और वो दो'

आयुष्मान खुराना की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने शुरूआती वीकेंड पर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कारोबारी दिनों की शुरूआत के साथ इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिली है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे दिन यानी पहले सोमवार को सिर्फ 3.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इससे पहले फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़, दूसरे दिन 5.75 करोड़ और तीसरे दिन 7.75 करोड़ रुपये कमाए थे। चार दिनों में फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब 20.75 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

फिल्म की कमाई में आई इस गिरावट को लेकर ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसकी राह और मुश्किल हो सकती है। अगले हफ्ते अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल सकता है। फिल्म में

आयुष्मान के साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, सूर्या और तृषा कृष्णन की फिल्म 'करप्पू' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने चौथे दिन 16.54 करोड़ रुपये का कारोबार किया और इसका कुल कलेक्शन 82.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 'करप्पू' अब तेजी से 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। उधर संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही है। चौथे दिन फिल्म ने सिर्फ 21 लाख रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन 2.16 करोड़ रुपये हो गया है।

पोस्ट को लेकर उठे सवालों पर सलमान खान का रिएक्शन

सलमान खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को चिंता में डाल दिया था। अभिनेता ने लिखा था कि खुद के साथ रहने के दो तरीके होते हैं, 'अकेले' और 'तन्हा'। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर चचाओं का दौर शुरू हो गया और फैंस सलमान की मानसिक स्थिति को लेकर अटकलें लगाने लगे। बढ़ती चचाओं के बीच अब अभिनेता ने खुद सामने आकर पूरे मामले पर सफाई दी है। सलमान ने एक्स पर नई पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अरे यार, मैं अपने बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। जब मेरे पास इतना बड़ा और शानदार परिवार और दोस्त हैं

तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूं। आप लोगों की दुआओं और प्यार के साथ मैं अकेला नहीं हो सकता, वरना मैं सबसे बड़ा नाशुक्रा साबित होऊंगा। उन्होंने आगे मजाकिया अंदाज में कहा कि कभी-कभी लोगों के बीच रहकर थकान हो जाती है, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अभिनेता ने यह भी बताया कि उनकी पिछली पोस्ट को लेकर उनकी मां भी परेशान हो गई थीं। सलमान ने लिखा, इस बार कोई फोटो नहीं डाली तो ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा? चिल मारो यार। सलमान की इस सफाई के बाद फैंस ने राहत की सांस ली है। वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता इन दिनों निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'एसवीसी63' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। यह फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है।

'कान्स 2026' में जैकलीन फर्नांडिस का ग्लैमरस अंदाज

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने 'कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026' में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हुए एक बार फिर ग्लोबल फैशन आइकॉन के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। प्रतिष्ठित मिरेकल्स गाला में शामिल हुईं जैकलीन का पहला लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस खास मौके पर उन्होंने कैरोलिन कूट्योर की ब्लैक स्ट्रैपलेस मिनी ड्रेस पहनी, जिसमें एलिगेंस और मॉडर्न ग्लैमर का शानदार मेल देखने को मिला। टेक्सचर्ड डिटेलिंग और फिटेड सिल्हूट वाली इस ड्रेस ने उनके लुक को बेहद स्टाइलिश और आकर्षक बना दिया। अपने ऑल ब्लैक लुक को और खास बनाने के लिए जैकलीन ने डायमंड ज्वेलरी कैरी की, जिसने उनके रेड कार्पेट अपीयरेंस में लग्जरी और क्लासी टच जोड़ दिया। मिरेकल्स गाला को कान्स की सबसे एक्सक्लूसिव फैशन इवनिंग्स में गिना जाता है, जहां बेला हदीद, डेमी मूर और एड्रियाना लीमा जैसे कई अंतरराष्ट्रीय सितारे मौजूद रहे। खास बात यह रही कि इस प्रतिष्ठित इवेंट में जैकलीन फर्नांडिस इकलौती भारतीय सेलिब्रिटी के रूप में नजर आईं। पिछले कुछ वर्षों में अभिनेत्री ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने फैशन सेंस और आत्मविश्वास से अलग पहचान बनाई है। कान्स 2026 में उनका यह अपीयरेंस भी उसी सफर का एक और शानदार अध्याय माना जा रहा है। बॉलीवुड स्टार से ग्लोबल फैशन फेवरेट बनने तक, जैकलीन लगातार अपने इंटरनेशनल स्टाइल स्टेटमेंट से लोगों को प्रभावित कर रही हैं।

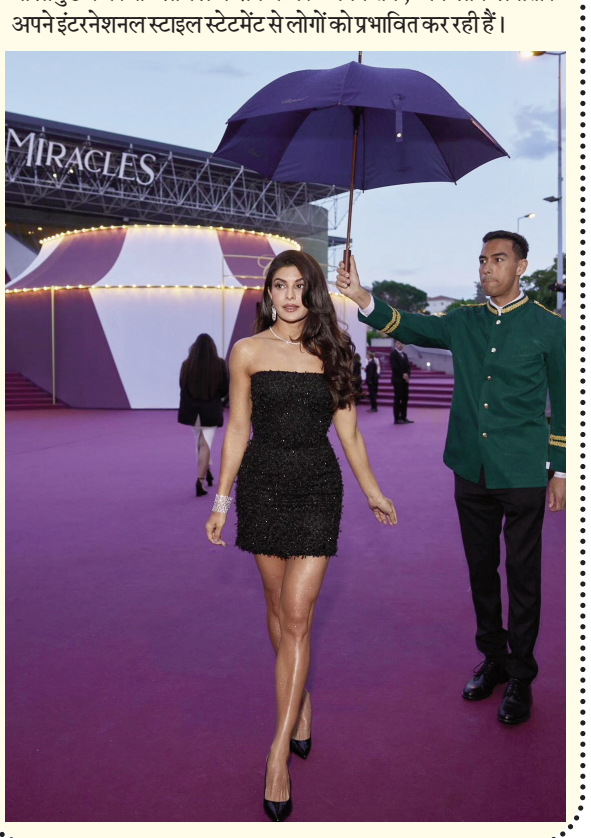

राष्ट्र निर्माण की दिशा में सशक्त कदम है जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा सहायता प्रदान करना : गुलाब चंद कटारिया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित साक्षरता कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर जरूरतमंद एवं मेधावी स्कूली विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान लगभग 450 वंचित विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी तथा अन्य अध्ययन सामग्री प्रदान की गई।

सभा को संबोधित करते हुए प्रशासक ने कहा कि बच्चों को शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना केवल दान का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी एवं सशक्त पहल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े सपने देखने, अनुशासित रहने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करने का आान किया। प्रशासक ने चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों के प्रदर्शन में लगातार हो रहे सुधार की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में सरकारी विद्यालयों का कुल परिणाम 87.25 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत 85.2 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि 57 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 348 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता एवं उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संरचित करियर काउंसलिंग कार्यक्रम प्रारंभ करने तथा उद्योगपतियों एवं अन्य हितधारकों का सहयोग जुटाने की दिशा में कार्य कर रहा है। प्रशासक ने भारत विकास परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 में मेधावी विद्यार्थियों के सहयोग हेतु 25 लाख रुपये निर्धारित करने के निर्णय की भी सराहना की। इस पहल के अंतर्गत कक्षा 9वीं, 11वीं एवं 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को सहायक पुस्तकें, प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति तथा व्यक्तित्व विकास सहयोग प्रदान किया जाएगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में वर्ष 1987 से भारत विकास परिषद के योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रशासक ने कहा कि परिषद की साक्षरता परियोजना से अब तक 22,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। समावेशी शिक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविक सामाजिक प्रगति तभी संभव है जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।

प्रशासक ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक संगठनों के ऐसे सहयोगात्मक प्रयास सरकारी पहलों को और अधिक सशक्त बनाते हैं। इस अवसर पर चंडीगढ़ प्रशासन के निदेशक स्कूल शिक्षा श्री नितिश सिंगला, भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अजय दत्ता, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री सुरेश जैन, साक्षरता परियोजना के निदेशक श्री अशोक कुमार गोयल तथा भारत विकास परिषद, चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री एम.के. विरमानी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सीएम विंडो मामलों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : उपायुक्त सतपाल शर्मा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

समीक्षा बैठक के बाद उपायुक्त ने अधिकारियों को जारी किए सख्त निर्देश

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ सीएम विंडो को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर सीएम विंडो पर विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के उपरांत पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा ने लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करें और उनके शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करें, ताकि लोगों की समस्याओं का तय समय सीमा में समाधान हो सके। उन्होंने कहा की सीएम विंडो मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

उन्होंने सभी विभागों को शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने तथा जल्द से जल्द एटीआर अपलोड करने के निर्देश भी दिए, जिससे शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविरों में भी सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है। नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनका मौके पर समाधान करते हैं।

बैठक में पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, नगर निगम आयुक्त विनय कुमार, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश जागृति, आरटीए हैरतजीत कौर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पाराशर, जिला वन मंडल अधिकारी विशाल कौशिक, तहसीलदार पंचकूला सुरेश कुमार, एमिनेंट पर्सन जस्मेर बंजारा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सोलिटेयर इंटरनेशनल स्कूल में पोक्सो जागरूकता शिविर आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

पोक्सो जागरूकता अभियान के तहत आज सोलिटेयर इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-20, पंचकूला में एक कानूनी जागरूकता शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को बाल संरक्षण कानूनों के प्रति संवेदनशील बनाना और बच्चों के अनुकूल कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस शिविर में स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अजय कुमार घनघस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पर केंद्रित एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा को समझने, अनुचित व्यवहार को पहचानने और बिना किसी डर या हिचकिचाहट के किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की तुरंत रिपोर्ट करने के महत्व पर जोर दिया। अपने संबोधन के दौरान, सीजेएम ने छात्रों के साथ एक प्रश्न-उत्तर सत्र आयोजित किया। उन्होंने छात्रों को खुलकर बोलने और बच्चों के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित अपने संदेहों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न बाल-हितैषी योजनाओं और कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक किया, और हर बच्चे के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति संस्था की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कार्यक्रम का सोलिटेयर इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने स्कूल परिसर के भीतर इतनी महत्वपूर्ण जागरूकता पहल आयोजित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन गणमान्य अतिथियों, संसाधन व्यक्तियों, स्कूल प्रशासन और प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर पंचकूला में प्रशिक्षण बैठक आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जुलाई 2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए हरियाणा राज्य में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस कार्यक्रम की तैयारियों एवं फीडबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला पंचकूला में उपायुक्त कार्यालय के बैठक कक्ष में एक प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त श्री संतोष कुमार दूबे, सचिव, श्री संजय कुमार, अवर सचिव तथा श्री राज कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ने की। बैठक में श्री संयम गर्ग, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.), कालका, श्री चन्द्रकांत कटारिया, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.), पंचकूला, सुश्री जागृति, नगराधीश एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचकूला, श्री निखिल सिंगला, तहसीलदार, कालका एवं सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी-क 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, श्री सुरेश कुमार, तहसीलदार, पंचकूला एवं सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी-क 02-पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, श्री परम नंदन, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रायपुर रानी एवं सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी-क 01-कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, श्री हरदेव सिंह, नायब तहसीलदार, पंचकूला एवं सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी-क 02-पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, श्रीमती सुमन चौधरी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, पंचकूला सहित जिले की दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ सुपरवाइजर, बूथ लेवल अधिकारी तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों तथा विशेष सावधानियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

संक्षिप्त-समाचार

चार पंजाब कैडर के आईएएस प्रॉबेशनर – सुभरत सिंह बालोट, गुर्कनवाल सिंह, हिमांशु, और अदिबा आनम अशफाक अहमद – ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया से पंजाब लोक भवन, चंडीगढ़ में शिष्टाचार भेंट की। बातचीत के दौरान, सार्वजनिक सेवा, सुशासन, और राष्ट्र निर्माण में युवा प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई।

पीजीआई में इंटरनेशनल नर्सेज वीक संपन्न

चंडीगढ़। पीजीआई के नर्सिंग विभाग द्वारा 12 से 18 मई तक इंटरनेशनल नर्सेज वीक का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम हमारी नर्सें, हमारा भविष्यः सशक्त नर्सें जीवन बचाती है रखी गई, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना और उन्हें सशक्त बनाने के महत्व को उजागर करना था। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरूआत 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे के आयोजन के साथ हुई। इस अवसर पर पीजीआईएमईआर के निदेशक प्रो. विवेक लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. पंकज अरोड़ा सम्मानित अतिथि रहे। 13 मई को न्यू ओपीडी में विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर जागरूकता व्याख्यान (हेल्थ टॉक्स) आयोजित किए गए, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। इसी दिन रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 नर्सिंग अधिकारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। 15 मई को कार्यक्रम की थीम हमारी नर्सें, हमारा भविष्यः सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं पर आधारित एक संगोष्ठी (सिम्पोजियम) आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रो. अशोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वक्ताओं ने नर्सिंग पेशे की चुनौतियों, नर्सों की भूमिका और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की तथा थीम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। हुआ। समारोह में प्रो. संजीव हांडा, सब डीन (एकेडमिक्स) एवं विभागाध्यक्ष, त्वचा रोग विभाग मुख्य अतिथि रहे, जबकि प्रो. अशोक कुमार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं विभागाध्यक्ष, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य नर्सिंग अधिकारी (कार्यवाहक) जसपाल कौर ने स्वागत संबोधन के साथ इंटरनेशनल नर्सेज वीक की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सप्ताहभर आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले नर्सिंग अधिकारियों को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

काजमपुर और रायपुर रानी में अवैध निर्माण ध्वस्त

पंचकूला । उपायुक्त पंचकूला श्री सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) श्रीमती बबीता गुप्ता के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम द्वारा अर्बन एरिया पंचकूला में बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव काजमपुर में 1 अवैध कॉलोनी में दुकान और चारदीवारी व गांव रायपुर रानी में 2 अवैध कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को जेसीबी द्वारा धवस्त किया गया। उक्त कार्यवाही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, श्री नरेन्द्र कुमार एसडीई, पंचायती राज, श्री अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकर, पंचकूला श्री डिम्पी राठी, सहायक नगर योजनाकर, पंचकूला एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई। जानकारी देते हुए डीटीपी श्रीमती बबीता गुप्ता ने बताया कि कोई भी निर्माण या कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति से किसी प्रकार का अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करता पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही जारी रखी जाऐगी। उन्होंने आम जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग से सीएलयु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना कोई भी निर्माण व अनाधिकृत कॉलोनी विकसित न करें।

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 की तैयारियां शुरू

पंचकूला। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के उपलक्ष्य में महानिदेशक आयुष विभाग हरियाणा श्री संजीव वर्मा के निदेर्शानुसार जिला प्रशासन पंचकूला एवं आयुष विभाग के द्वारा 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। डा दिलीप कुमार मिश्रा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, पंचकूला की अध्यक्षता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2026 के अवसर पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तहत 20 मई तक प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक स्कूलों के प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, पीटीआई व डीपीआई को आयुष विभाग के योग विशेषज्ञा व खेल विभाग के योग प्रशिक्षकों द्वारा योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी क्रम में आज ताउ देवी लाल स्टेडियम, सैक्टर-3, पंचकूला में लगभग 65 से अधिक स्कूलों के प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, पीटीआई व डीपीई को योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण शिविर का आंरभ प्रार्थना मंत्र के उच्चारण से किया गया । तदोपरांत योग क्रियाओं जैसे ताडासन, वृक्षासन, पादहस्त, अर्धचक्रासन, वज्रासन, उत्तानमंडुक, उष्ट्रासन, वक्रासन, मक्रासन, शलभासन, सेतुबंध, उत्तानपादासन, पवनमुक्त, अर्धहलासन, अनुलोम विलोम, कपालभाती, भ्रामरी का अभ्यास करवाते हुए इन यौगिक क्रियाओं द्वारा होने वाले लाभों की भी जानकारी दी गई। इस योग शिविर में आयुष विभाग के योग विशेषज्ञा रितू मित्तल उपस्थित रही।

हरियाणा ने टीबी मुक्त भारत अभियान को दी रफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

देश को तपेदिक (टीबी) से मुक्त करने के संकल्प को और मजबूत करते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, डॉ. मनीष बंसल और मिशन चेतना फाउंडेशन प्रमुख सुश्री मनीषा चैधरी ने आज स्वास्थ्य भवन परिसर, सेक्टर-6 से बाल टीबी मरीजों के लिए विशेष फोर्टिफाइड पोषण आहार पैकेट ले जा रहे एक समर्पित वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पोषण वितरण का यह महत्वपूर्ण अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस सामूहिक प्रयास में मिशन चेतना फाउंडेशन और राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया ने निक्षय मित्र के रूप में आगे आते हुए हरियाणा राज्य के तीन जिलो में 70 बाल टीबी मरीजों (उम्र 0-18 वर्ष) को 6 महीने की अवधि के लिए गोद लिया है जिसमे पंचकूला के 20, अंबाला के 20 और यमुनानगर के 30 मरीज शामिल है।

समाज और कॉपोरेट से जनभागीदारी की अपील

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने इस अनूठी मानवीय पहल के लिए मिशन चेतना फाउंडेशन और राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर अधिकारियों ने आम जनता से एक भावुक अपील की। टीबी के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ, हमें जनभागीदारी और सामाजिक अपनेपन की भी जरूरत है। हम आम नागरिकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और कॉपोरेट घरानों से बड़े स्तर पर आगे आने, अपने-अपने जिलों में टीबी मरीजों को गोद लेने और उन्हें पोषण व जांच सहायता प्रदान करने का आग्रह करते हैं। सबके साथ मिलकर ही हम अपनो को सुरक्षित कर सकते हैं और हरियाणा से टीबी को जड़ से मिटा सकते हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. मनीष बंसल ने इस बात पर जोर दिया कि टीबी के सफल इलाज के लिए पर्याप्त पोषण बेहद बुनियादी जरूरत है। टीबी के इलाज के लिए मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को बढ़ाना और दवाइयों का नियमित सेवन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इन युवा मरीजों के दैनिक आहार में वैज्ञानिक रूप से तैयार, पोषक तत्वों से भरपूर भोजन को शामिल करके, हम इलाज बीच में छोड़ने की दर (डिफॉल्ट रेट) को कम कर रहे हैं और मरीजों के तेजी से ठीक होने का रास्ता साफ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग आम नागरिकों से इस जनभागीदारी आंदोलन से जुड़ने और टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील करता है।

नन्हे योद्धाओं के लिए वैज्ञानिक पोषण सहायता

वितरित की जा रही पोषण सहायता में राइज अगेंस्ट हंगर इंडिया के प्रीमियम, फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल पैकेट शामिल हैं, जिन्हें बच्चों की पसंद और स्वाद को ध्यान में रखकर विशेष रूप से तैयार किया गया है। स्टेट टीबी सेल द्वारा स्वयं तैयार और स्वाद-परीक्षण किए गए ये पैकेट बच्चों के लिए बेहद स्वादिष्ट और सुपाच्य हैं। इस भोजन में उच्च गुणवत्ता वाले चावल, लाल मसूर की दाल और सूखी सब्जियां (गाजर, पत्तागोभी, मटर और धनिया) शामिल हैं। यह आहार बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जबरदस्त मजबूती देता है। इसके प्रत्येक पैकेट से लगभग 2,000 किलो कैलोरी ऊर्जा और 112 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है। इसमें एक अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट (सूक्ष्म पोषक तत्व) का पाउच भी दिया गया है।

निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत खंड बरवाला और रायपुररानी की बीपीआईयू सम्पन्न

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत बरवाला व रायपुर रानी खंड की ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की मई माह की मासिक बैठकों का आयोजन सम्बंधित खंड शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में समापन हुओ। बैठकों का आयोजन खंड बरवाला व रायपुर रानी दोनों खंडों में खंड शिक्षा अधिकारी संजू शर्मा की अध्यक्षता में बी पी आई यू का आयोजन किया गया जिसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिव्या व गुरुसेवक सिंह नें पीपीटी के माध्यम से क्लस्टर व विद्यालय वार एनरोलमेंट प्रगति, मेटर,मॉनिटर विजिट कंप्लायंस, क्लास रेडीनेस कार्यक्रम प्रगति, मेंटर रहित क्लस्टर की कार्ययोजना व विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों की के आबँटन को विस्तार से प्रस्तुत किया। खंड बरवाला की बी पी आई यू में प्रिंट रिच कक्षा कक्ष प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुमन लता राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला खटौली, रेखा ठाकुर राजकीय प्राथमिक पाठशाला नग्गल, श्री लता राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला बरवाला,ममतेश व रीटा, राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला भरेली रायपुर रानी की बी पी आई यू में अमिता पी.आर. टी. रा. प्रा. पा. जासपुर, नरेंद्र पाल पी.आर. टी. रा. प्रा. पा. गोलपुरा, रीना देवी पी.आर. टी. रा. प्रा. पा. भूड, शालिनी पी.आर. टी. रा. प्रा. टाबर आदि को सम्मानित किया गया।

नवाजा

बच्चों के सपनों के लिए जूझती रहीं माएं, मंच पर बही भावनाओं की धारा, तालियों के बीच भी छलके आंसू

संघर्ष, त्याग और ममता की मिसाल बनीं 10 माओं को राज्यपाल ने किया सम्मानित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

जिंदगी की कठिन राहों में जब हालात ने कदम-कदम पर इम्तिहान लिए, तब भी कई माओं ने हार मानने के बजाय अपने बच्चों के सपनों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। किसी ने गरीबी से जंग लड़ी, किसी ने अकेले संघर्ष कर परिवार संभाला तो किसी ने अपने हिस्से की खुशियों का त्याग कर बच्चों का भविष्य संवार दिया। ऐसी ही साहस, त्याग और ममता की मिसाल बनीं 10 संघर्षशील माओं को मंगलवार को आयोजित 13वें मां सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने माओं को सम्मानित कर उनके संघर्ष को नमन किया।

मानव मंगल ग्रुप ऑफ स्कूल्स और डॉ. जीसी मिश्रा मेमोरियल एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मानव मंगल स्मार्ट स्कूल में आयोजित समारोह भावनाओं से सराबोर रहा। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से आईं माओं की संघर्षगाथाएं सुनकर सभागार में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। जब मंच से इन माओं के जीवन संघर्ष और समर्पण की कहानियां सुनाई गईं तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। हर कहानी यह एहसास करा रही थी कि मां केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि वह अटूट शक्ति है, जो हर तूफान अपने ऊपर झेलकर भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है।

समारोह की शुरूआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर चंडीगढ़ की पलविंदर कौर, राज कुमारी और सुनैना देवी, पंजाब के बुढलाडा की मंजीत कौर, मोहाली की मनप्रीत शर्मा, न्यू चंडीगढ़ की अंजू भाटिया, हरियाणा के करनाल की गिन्नी और कुरुक्षेत्र की बलजीत कौर को सम्मानित किया गया। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए मुल्लांपुर निवासी कर्नल मनप्रीत सिंह की मां मंजीत कौर को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं, एसओएस चिल्ड्रेन विलेज इंडिया, राजपुरा की रीटा दास को मदर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मां सम्मान समारोह को समाज के लिए प्रेरणादायी पहल बताते हुए कहा कि मां वह शक्ति है, जो अपने बच्चों को केवल जन्म ही नहीं देती, बल्कि उन्हें संस्कार, शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्षों से लड़ने का साहस भी देती है। उन्होंने कहा कि मां चाहे किसी साधारण व्यक्ति की हो या किसी महान हस्ती की, हर जीवन में मां का स्थान सर्वोच्च होता है और वही सबसे अधिक दिलों पर राज करती है। मां की हिम्मत, त्याग और सहनशीलता का कोई मुकाबला नहीं। भगवान ने मां को ऐसी अद्भुत शक्ति दी है कि वह हर संकट का निडर होकर सामना कर सकती है। भारत का इतिहास भी मातृत्व की महान गाथाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान भी मां की कोख से जन्म लेते हैं, इसलिए मां की कोख को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मां ही बच्चों में संस्कार, अनुशासन और अच्छे गुणों का संचार करती है। अपने आंचल की छांव में वह बच्चों की हर पीड़ा को दूर करने का प्रयास करती है। गरीब से गरीब मां भी कठिन परिस्थितियों में मेहनत कर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और ऊंचे पदों तक पहुंचाने का सपना साकार करती है। समारोह में मानव मंगल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर संजय सरदाना, एसोसिएट डायरेक्टर संकल्प सरदाना और समर्थ सरदाना, मानव मंगल हाई स्कूल सेक्टर-21 की ब्रांच डायरेक्टर अंजलि सरदाना तथा डॉ. जीसी मिश्रा मेमोरियल एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी मयंक मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन उमा महाजन ने किया। उल्लेखनीय है कि डॉ. जीसी मिश्रा मेमोरियल एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मानव मंगल स्मार्ट स्कूल के सहयोग से पिछले 14 वर्षों से मदर्स डे के अवसर पर मां सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त डॉ. जीसी मिश्रा की स्मृति में उनके पुत्र मयंक मिश्रा ने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी।